RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

01-15 अक्तुबर, 2018

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 6/ पृष्ठः 16
मूल्यः ₹ 25/-

www.therievtimes.com

नशे के खिलाफ सरकार का ज़ीरो टॉलरैंस, संस्था को मिलेगा सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग

राज्य स्तरीय नशामुक्त अभियान संस्था का प्रशंसनीय प्रयास : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश भर से आए प्रतिभागी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

द रीव टाइम्स (हेम राज चौहान)

नशा मुक्त हिमाचल अभियान 'ज़िंदगी जियें–नशे को नहीं' के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय संभाषण प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और संस्था के हिमाचल भर में चल रहे सामाजिक एवं सतत विकास कार्यों एवं सेवाओं को खूब सराहा। उन्होंने 5 सितंबर से संस्था द्वारा संचालित नशामुक्त अभियान के राज्य स्तरीय संभाषण प्रतियोगिता में विजेताओं एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृतिचिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर नगर निगम शिमला कुसुम सदरेट, उप महापौर राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संस्था ने हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ विद्यालयों में जो प्रतियोगिताऐं आयोजित की हैं, उनमें नशे के खिलाफ एक मुहिम बनी है और प्रदेश सरकार ऐसी संस्थाओं के प्रयासों को भविष्य में भी सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के दलदल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सरकार ज़ीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने की बात कह चुकी है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ इसके लिए प्रदेश सरकार की बैठक में संयुक्त प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में युवाओं और स्कूली बच्चों को इस नशे की फांस से बचाने और एक स्वस्थ हिमाचल बनाने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक प्रयासों के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए आईआईआरडी द्वारा पूरे प्रदेश में स्वैच्छिक रुप से नशामुक्त अभियान एक मील का पत्थर है और संस्थाओं के ऐसे प्रयासों की सरकार न केवल प्रशंसा करती है बल्कि भविष्य में शिक्षा विभाग या सरकार के अन्य स्तरों पर यदि संस्था को कोई भी सहायता या सहयोग वांछित होगा, उसमें सरकार एक क़दम आगे आकर साथ देगी। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आए प्रतियोगी विद्यार्थियों के संभाषण को सुनकर भी नई पीढ़ी की सोच और उनके विचारों को सराहा।

क्या कहता है सर्वे

इस अभियान के साथ–साथ ही आईआईआरडी ने एक ऑनलाईन सर्वे करवाकर सभी लोगों को इसमें शामिल होने का अवसर दिया विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों को। इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

बच्चे किस प्रकार के नशे के शिकार हो सकते हैं, जैसा कि आपको लगता है ?

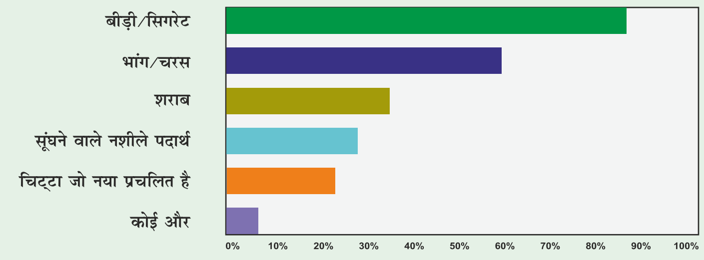

क्या आपके संज्ञान में ऐसे भी बच्चें हैं जिन्हें आपको लगता है कि नशे पर काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है

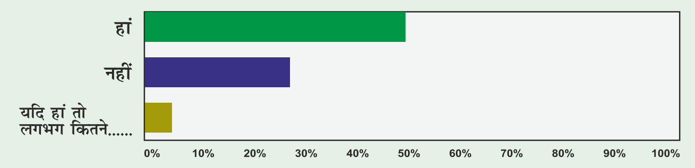

आपके अनुमान के अनुसार सम्बंधित स्कूल के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे नशे के शिकार होने की संभावनाएं हैं।

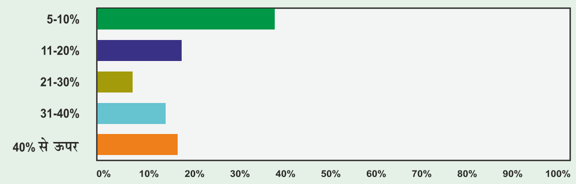

क्या कहते हैं अभियान के संचालक एवं प्रबन्ध निदेशक

नशामुक्त हिमाचल अभियान 'ज़िंदगी जियें–नशे को नहीं' के प्रणेता एवं संचालक व प्रबन्ध निदेशक आईआईआरडी डॉ0 एल सी शर्मा ने इस अभियान की बारीकियों को सामने रखते हुए बताया कि इस अभियान के चार चरण है तथा यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण रहा जिसमें पूरे हिमाचल को शामिल किया गया था। सैंकड़ों स्कूलों के बच्चों ने इसमें विभिन्न माध्यमों से शिरकत की तथा राज्यस्तर की इस संभाषण प्रतियोगिता तक स्थान बनाया। इसके बाद दूसरे चरण पर अभियान आरम्भ किया जाएगा जिसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने भी हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अलावा अब युवाओं को फोकस कर समस्या के निदान तक पंहुचने का संस्था प्रयास करेगी। इसके लिए खाका तैयार किया जा चुका है।

आईआईआरडी की सेवाऐं प्रशंसनीय : महापौर

शिमला नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने आईआईआरडी की सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस संस्था ने स्वयं को प्रदेश में अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता और बदलाव के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी संस्था के अनेक कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुकी हैं तथा मिशन रीव और आईआईआरडी की गतिविधियों को समीप से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। नशे जैसी गंभीर चुनौती को स्वीकार कर इस संस्था ने प्रदेश भर में अभियान के माध्यम से अच्छी पहल की है। नगर निगम शिमला इस अभियान में हरसंभव सहयोग के लिए तत्पर है।

जवाबदेही काफी नहीं, मार्गदर्शन भी जरूरी- सीएस

हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही की कमान आख़िरकार एक तेज तर्रार, अनुभवी और शांत स्वभाव के अधिकारी बृज कुमार अग्रवाल के हाथों में प्रदेश सरकार ने हाल ही में सौंपी है। बी.के. अग्रवाल आमतौर पर स्टीक और त्वरित निर्णय लेने के साथ ही अपनी दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते हैं। बतौर मुख्य सचिव हिमाचल को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और सभी को साथ लेकर कैसे वह सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचाएंगे, इस बारे में 'द रीव टाइम्स' सहायक संपादक **अंजना ठाकुर** ने उनसे विस्तृत बात की:

सवाल - बतौर मुख्य सचिव हिमाचल को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?

जवाबः मेरी पहली प्राथमिकता सरकार और आम लोगों के बीच की खाई को पाटना है। सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि तय समय के भीतर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इसके लिए किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।

सवाल : योजनाओं का लाभ तय समय में लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी?

जवाबः अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने काम को लेकर स्वयं जवाबदेह रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम के लिए जबावदेही से ज्यादा, सही मार्गदर्शन जरूरी है। इसके अलावा मिलकर काम करने से किसी भी योजना को सिरे चढ़ाया जा सकता है।

सवालः हिमाचल में प्रशासनिक अधिकारियों की पहले कमी है, उस पर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, क्या काम का बोझ अधिक है ?

जवाबः ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक सेवा का अहम हिस्सा है। हिमाचल में जो अधिकारी हैं वह बेहतर काम कर रहे हैं। ये सही है कि कुछ अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये अधिकारी इन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम है और बेहतर काम हो रहा है।

सवाल : राज्य पर कर्ज का बोझ है, किस तरह बोझ के साथ आगे बढ़ेंगे

जवाबः राज्य की आय बढ़ाना चुनौति तो है क्योंकि प्रदेश की परिस्थितियां दूसरे राज्य से काफी अलग है। यहां की भौगोलिक स्थिति और यहां का जीवन मुश्किल है। फिर भी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी योजनाओं को सिरे चढ़ाया जाए जिनसे राज्य की आमदन बढ़ने के साथ–साथ आम आदमी की आर्थिकी भी मजबूत हो सकें।

शेष पेज 3 पर

मिशन रीव : वर्षगांठ पर अर्श से फर्श का सफरनामा

द रीव टाइम्स (हेम राज चौहान)

ग्रामीण भारत में आमजन की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मानचित्र अपनी दृष्टि में उकेरे अपने अनुपम एवं अनूठे प्रयोग को आत्मसात किए मिशन रीव अपनी वर्षगांठ पर लोगों के सपनों को साकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है । मिशन रीव गांवो को जोड़ता और लोगों का सबसे अच्छा दोस्त बनकर अपनी बेहतरीन सेवाओं के साथ कदमताल कर रहा है । 2 अक्तुबर 2017 को एक विचार ने जन्म लिया । इस विचार के जनक डॉ0 एल सी शर्मा इसे जीवन का ध्येय बनाकर सामने लाए । उस विचार का जब मंथन हुआ तो मथते–मथते बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई ।

विचार से व्यवहार तक

मिशन रीव का उद्भव एक विचार से हुआ जिसके फलीभूत होने के लिए वर्षों का संघर्ष, अनुसंधान एवं ग्रामीण परिस्थितियों का गहन अध्ययन इसके मूल में था । विचार पर सहमति के बाद इसका एक ढांचा तैयार हुआ और इसके लिए जो भी आवश्यक पहल की

दरकार थी उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रादेशिक स्तर पर व्यवहारिकता में लाया गया ।

रुरल कॉनक्लेव: परंपरा से हटकर एक नया कदम

मिशन रीव की लॉचिंग भी इसके अनूठे होने के जैसी ही बिल्कुल अलग तरीके से की गई । क्योंकि हम गांव की बात करते हैं.....इसलिए गांव की बात गांव में ही करने के उद्देश्य से रुरल कॉनक्लेव को भी दूरदराज के गांव में करने का निर्णय हुआ । ऐसे कॉनक्लेव अमूमन पौश क्षेत्र में या पांच सितारा होटल में ही रिवाजन किए जाते रहे हैं । किंतु इसे शिमला में रामपुर के शोली गांव में आयोजित किया गया । यह अपने आप में अनूठा प्रयास मिसाल बन गया ।

भारत सरकार ने की तारीफ-केन्द्रिय मंत्री ने किया आगाज़

मिशन रीव अपने वृहद स्वरुप के अनुसार ही जनमानस में लॉच भी हुआ । केन्द्रिय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने शिमला में इसके आगाज़ के साथ ही इस मिशन को दूरगामी सोच और लोगों को सीधा जोड़ने वाला कहा । उन्होंने कहा कि इस मिशन से सरकार की नीतियों को घर–घर तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी । उन्होंने इस मिशन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल में इसके सफल होने पर इसे पूरे भारत में भी लागु करने में सरकार सहयोग करेगी ।

हिमाचल में बड़ा नेटवर्क : पांच हज़ार लोगों को प्रथम चरण में रोजगार

मिशन रीव ने 50 हज़ार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के अंतर्गत प्रथम चरण में ही विभिन्न स्तरों एवं पारुपों में पांच हज़ार लोगों को रोजगार प्रदान किया । प्रदेश की सभी पंचायतों को मिशन रीव से जोड़कर लोगों को सभी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को साझा करने का लक्ष्या रखा गया ।

जहां 2 अक्तुबर 2017 को एक विचार केवल राज्य,ज़िला एवं ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के साथ चलन में था, वहीं 2 अक्तुबर 2018 के एक वर्ष के अंतराल में आज मिशन रीव का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है जिसमें शामिल हैं :

- राज्य सचिवालय का गठन
- प्रदेश के सभी ज़िलों में 52 खण्ड स्तरीय कार्यालय स्थापित
- प्रदेश के सभी ज़िलों में 48 उप–खण्ड स्तरीय कार्यालय स्थापनाधीन
- प्रदेश में समस्त सेवाओं से संबद्ध 10 सेवा प्रभाग गठित

इसके अलावा हमारी सेवाओं में :

- किसानों के लिए रीव जैविक खाद(एलगे उर्वरक मिश्रित) निर्माण का बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया जिसमें जैविक कृषि के क्षेत्र में रीव की सेवाओं को विभिन्न माध्यमों से पूरा किया जा रहा है । इसके लिए बेहतरीन गुणवत्ता की रीव जैविक खाद तैयार किया जा रहा है तथा एलगे उर्वरक मिश्रण को मिला इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी की गई है ।
- प्रदेश के 12 ज़िलों में मृदा जांच मशीने अब स्थापित की गई है । रीव सेवाकर्मी किसान के खेत में जाकर मिट्टी के सैंपल लेकर उसी समय परीक्षण कर उसे रिपोर्ट देते हैं जिसके हिसाब से किसान फसलें उगाने में कामयाब होने लगा है ।
- मिशन रीव के अंतर्गत ही प्रदेश में मिशन की गतिविधियों एवं आमजन की आवाज़ बनने के लिए अपना पब्लिकेशन आरंभ किया गया तथा पाक्षिक विकासात्मक द रीव टाइम्स समाचार पत्र प्रदेश का एकमात्र सर्वोत्तम गुणवत्ता के पृष्ठों एवं विषयवस्तु के साथ प्रकाशित हो रहा है जिसे प्रदेश भर में सराहना मिल रही हैं ।
- मिशन रीव एक विचार के बाद एक साधारण कागज़ पर उकेरा गया था किंतु 2 अक्तुबर 2018 तक इसकी समस्त गतिविधियों को ऑनलाईन पोर्टल पर लाया जा चुका है । मिशन रीव की भर्ती प्रकिया, इसके समस्त कार्य, सेवाऐं, डिविजन तथा संबन्धित अन्य समस्त सामग्री अब ऑनलाईन है । यहां तक कि प्रत्येक छोटे से बड़े साक्षात्कार एवं समस्या अथवा आवश्यकताओं को ऑनलाईन ही पूर्ण किया जा रहा है । यही मिशन रीव की पारदर्शिता का अनुपम उदाहरण है ।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 अक्तुबर 2018 तक आते–आते एक वर्ष में सबसे प्रगतिशील सेवाऐं लोगों के मध्य है । पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के भिन्न–भिन्न प्रारुपों में मिशन रीव ने ऐतिहासिक सफलता की ओर कदम बढ़ाया है । इसमें रीव क्लिनिक, जेनेरिक औषधी केन्द्र जो कि प्रदेश में 300 से अधिक के खोलने का लक्ष्य हैं जिसमें 12 जेनेरिक औषधी केन्द्र खोले जा चुके हैं , स्वास्थ्य स्लेट चैकअप जिसमें 14 प्रकार के महत्वपूर्ण टैस्ट सेवाऐं आदि गांव–गांव में लोगों को सुलभता से प्राप्त होने की प्रकिया में हैं । सस्ता उपचार, सस्ती औषधी और सरल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिशन रीव लक्ष्य साध रहा है ।
- सभी कार्यालय आवश्यक सुविधाओं एवं उपकरणों से लैस किए जा चुके हैं । रीव सेवाकर्मियों को भी इंटरनैट सुविधा प्रदान की गई है । लगभग 80 प्रतिशत से अधिक के कार्य ऑनलाईन किए जा चुके हैं ।

सामुदायिक संबद्धता :

- मिशन रीव की सदस्यता आज चार हज़ार का आंकड़ा छू चुका है । इन सदस्यों में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने स्वयं को जोड़ा है तथा मिशन की सेवाओं को स्वीकार किया है ।
- 30,000 से अधिक लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है

प्रभाव :

- अब तक 6259 सेवाओं को लोगों को प्रदान किया जा चुका है
- अब तक 16,789 मरीज़ों का डायगनॉज, चैकअप एवं उपचार किया जा चुका है ।
- 5000 से अधिक लोगों को प्रथम चरण में रोजगार
- अब तक 259 कार्यक्रमों का आयोजन

सुनहरे भविष्य की ओर :

- पूरे प्रदेश में प्रत्येक पंचायत, ब्लॉक, ज़िला स्तर में सलाहकार बोर्ड गठित किए जा रहे हैं ।
- पंचायत में दो पद रीव को–ऑर्डिनेटर के भरे जाना प्रस्तावित है
- ऑनलाईन सेवाओं को शत–प्रतिशत करने का लक्ष्य
- ग्रामीण उत्पादों को किसान से खेत में ही खरीद कर बाज़ार तक पहुंचाने का लक्ष्य
- बाहरी उत्पादों को गुणवत्ता एवं सस्ते दामों पर लोगों को मिशन रीव से उपलब्ध करवाना ।

हमारा नेटवर्क

हमारा नेटवर्क
राज्य सचिवालय का गठन
प्रदेश के सभी ज़िलों में 52 खण्ड स्तरीय कार्यालय स्थापित
प्रदेश के सभी ज़िलों में 48 उप-खण्ड स्तरीय कार्यालय स्थापनाधीन
प्रदेश में समस्त सेवाओं से संबद्ध 10 सेवा प्रभाग गठित

सेवाऐं
स्वास्थ्य स्लेट
मोबाईल लैब
जेनेरिक औषधी केन्द्र
रीव जैविक खाद
जैव कीटनाशक
कैटल फीड सप्लिमैंट
मृदा जांच
मशरुम उत्पादन
आवश्यकता आधारित सेवाऐं
बाज़ार से सस्ते दामों पर उत्पाद सेवाऐं
द रीव टाइम्स प्रकाशन

एक वर्ष-एक नज़र : मिशन रीव का सामान्य खाका

- मई 2017 : आईआईआरडी के स्टाफ के साथ मंथन
- मई 2017 : विभिन्न वर्गो के साथ विषयवस्तु पर सहमति बारे चर्चा
- जून 2017 : आईआईआरडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस की मिशन बारे स्वीकृति
- जुलाई 2017 : राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत से मिशन बारे संदेश
- जुलाई 2017 : हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक तथा मिशन बारे प्रस्तुतिकरण
- जुलाई 2017 : मिशन रीव के विभिन्न पदों हेतु विज्ञप्ति तथा अधिसूचना
- अगस्त–सितंबर 2017 : राज्य, ज़िला तथा ब्लॉक समन्वयकों का चयन
- सितंबर 30 से 2 अक्तुबर 2017 : मिशन रीव का केन्द्रिय कृषि तथा पंचायतीराज राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला द्वारा विधिवत शुभारंभ
- अक्तुबर 2, 2017 : तीन दिवसीय रुरल कनक्लेव का समापन तथा चयनित टीम का कार्य संबंधित प्रशिक्षण
- अक्तुबर–नवंबर 2017 : पंचायत फेसिलिटेटर का चयन तथा प्रशिक्षण
- फरवरी 26, 2018 : मिशन की हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर द्वारा सेवाओं का शुभारंभ
- मई 2018 : प्रदेश 52 ब्लॉक स्तर के कार्यालयों की स्थापना
- जुलाई 16, 2018 : सेवाओं में जेनेरिक औषधी केन्द्र का हिमाचल के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं वर्तमान मुख्य सचिव बी के अग्रवाल द्वारा ऑनलाईन शुभारंभ
- अक्तुबर 2, 2018 : मिशन के एक वर्ष पूरे होने पर प्रदेशव्यापी नशामुक्त अभियान के प्रथम चरण के समापन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता

जन सहयोग से एक वर्ष का मिशन रीव सफरनामा
सेवा समर्पण से हर समस्या को समाधान तक लाना

नशे के खिलाफ आईआईआरडी के साथ आया समाज

टीम रीव, शिमला

आईआईआरडी की ओर से बीते पांच सितंबर को नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान की चौतरफा सराहना हो रही है। लोग खुलकर नशे के खिलाफ आईआईआरडी के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं।

महिला मंडल, स्वंय सहायता समूह, शिक्षक, विद्यार्थी और प्रबुद्ध समाज, सभी अभियान का हिस्सा बन रहे है। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर रैलियों के माध्यम से, कहीं पर भाषण तो कहीं पर चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। हाल ही में शिमला के साथ लगते उपनगर, पंथाघाटी, अन्नाडेल, में भी संयोजक सीमा चौहान की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। पंथाघाटी में इस मौके पर स्वंय सहायता समूह की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। लोगों खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

वहीं इसी कड़ी में अन्नाडेल स्थित चित्कारा पार्क में भी विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अन्नाडेल के हर आयु वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नशे की कुरीति को दूर करने के लिए अपने–अपने विचार साझा किए और प्रदेश को नशामुक्त करने का संकल्प लिया। वही रोहडू के बारतु स्कूल में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें राजन ने पहला, अभिषेक ने दूसरा, साक्षी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम के दौरान स्थानिय पंचायत प्रधान ने संस्था के प्रयासो की सराहना की। इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन कोटखाई, जुब्बल समेत अन्य विभिन्न स्थानों पर किया गया।

पेज 1 का शेष

जवाबदेही काफी नहीं, मार्गदर्शन भी जरूरी- सीएस

सवाल : आप किसे अपना आदर्श मानते हैं?

जवाब : मेरे माता–पिता ही मेरे सबसे बड़े आदर्श रहे। उन्होंने मुझे बचपन में जो सीख दी वह आज भी मेरे जीवन में काफी महत्व रखती है।

सवाल- कोई संदेश जो आप सभी को देना चाहते हो?

जवाब: मेरा संदेश सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासियों के लिए है कि सभी मिलजुल और प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्य करें। उम्मीद करता हूं कि प्रदेश का विकास हर आदमी की पहली प्राथमिकता रहे और इसमें सभी सहयोग करें।

संक्षिप्त जीवन परिचय

बीके अग्रवाल का जन्म यूपी के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में 15 जून 1961 को हुआ। शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली से एमटेक और इग्नू से एमबीए किया। लोक प्रशासन में पंजाब विश्वविद्यालय से एमफिल की।

1983 में आगरा में आयकर विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त हुए। 1985 में आईएएस में हिमाचल काडर में चयन हुआ। शुरुआती पोस्टिंग दुर्गम क्षेत्र पच्छाद में सहायक आयुक्त के तौर पर हुई। आउटर सिराज आनी में सेवाएं दीं। केंद्र और राज्य में विभिन्न पदों पर रहे। बेहतरीन कार्य प्रणाली और अनुभव के बलबूते उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया।

अब बीके अग्रवाल से पूरे प्रदेश उम्मीद है कि वह बतौर मुख्य सचिव प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे और सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक निर्बाधित रूप से पहुंचाएंगे।

स्वास्थ्य स्लेट से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल

टीम रीव, शिमला/किन्नौर

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह किन्नौर में भी लोगों को भी यह सुविधा मिल रही है। घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने इसके चलते गांव में लोगों को काफी राहत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

मिशन रीव की यह सेवा किन्नौर के दुर्गम इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। हर घर में टेस्ट सुविधा देने के साथ ही गांव में स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से जांच शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। किन्नौर के पूह ब्लॉक की स्पीलो पंचायत में हाल की में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्पीलो पंचायत प्रधान समेत कई लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया और मिशन रीव की सेवाओं की सराहना की। स्पीलो की पंचायत प्रधान सरीता नेगी का कहना है कि पंचायत स्तर पर घर में आकर स्वास्थ्य जांच की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं थी। साधारण से टेस्ट के लिए भी लोगों को क्लीनिकों और अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही थी। लेकिन अब मिशन रीव के तहत घर में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से लोगों के स्वास्थ्य की जांच आसान हो गई और इससे पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। इसी तरह प्रदीप नेगी, एचडी नेगी और देवा नेगी ने भी मिशन रीव के तहत पंचायतों में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि किन्नौर के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब रहने से स्वास्थ्य केंद्रों तक समय पर पहुंच पाना मुश्किल होता हैं। कई बार साधारण टेस्ट कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मिशन रीव गांव के लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है।

मोबाइल लैब में दो सौ से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य जांचा

आईआईआरडी शिमला की ओर मिशन रीव के तहत प्रदेश के उन क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है जहां आमतौर पर अन्य संस्थाएं नहीं पहुंच पाती। मिशन रीव के तहत हाल ही में रोहडू, छौहारा की ग्राम पंचायत काशधार समेत अन्य स्थानों पर मोबाइल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली बच्चों में एचबी और ब्लड ग्रुप की जांच की गई। इसके साथ ही पंचायत में लोगों के बेसिक ब्लड टेस्ट किए गए और स्वास्थ्य संबंधि परामर्श भी दिया गया। पिछले महज चार माह के भीतर जिला शिमला में ही पांच हजार से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उनके घरद्वार पर ही देने में मिशन रीव सफल रहा है। इस दौरान शिमला

ठियोग, शोली, रामपुर, रोहडू, छवारा, मूलकोटी, जुब्बल, व अन्य स्थानों पर भी इस तरह के शिविरो का आयोजन किया गया।

आईआईआरडी के इस प्रयास की प्रशंसा भी ग्रामीण क्षेत्रों मे खूब की जा रही है। एचओडी आईआईआरडी मिशन रीव पैथ लैब डाक्टर केआर शांडिल ने बताया कि इस शिविर में मोबाइल बाइक लैब से 5 हजार से अधिक लोगों के रक्त की जांच की जा चुकी है। इनमें मिशन रीव के सदस्यों को निशुल्क सेवाएं दी गई। इसके लिए आईआईआरडी शिमला कार्यालय में लैब तकनिकी सहायक को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। मिशन रीव पैथ लैब से ब्लॉक स्तर पर 70 से अधिक टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध है।

कोमली बैंक में महिलाओं ने नशे के खिलाफ उठाई आवाज

टीम रीव, शिमला

प्रदेश में नशे के ख़िलाफ आह्वान और मुहिम के तहत नशामुक्त हिमाचल के लिए सभी वर्गों ने आगे आकर इसका समर्थन किया है और अपने–अपने तरीके से इसके लिए सेवाऐं दे रहे हैं। आईआईआरडी संस्था के इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम को शिमला के कोमली बैंक में भी महिलाओं ने बुलंद आवाज़ के साथ मनाया। यहां की महिलाओं ने इस पर न केवल नशे के खिलाफ बात रखी बल्कि लोगों को जागरुक करने के लिए पंपलैटस भी बांटे जिसमें नशे से होने वाले नुकसान और बचाव पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। कार्यक्रम में स्वैच्छिक कार्यकर्ता सीमा चौहान ने बताया कि नशे से जीवन तो विनाश की स्थिति में आ ही जाता है परन्तु सबसे अधिक इसका खामियाजा बच्चों एवं महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। इस लिए इस अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में उदघोष संस्था ने सहयोग दिया।

इस कार्यक्रम में 60 लोगों ने भाग लिया। सबसे बुजुर्ग महिला ने भी कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ग़लत रास्ते पर चल रहे हैं और आज परिवार इस कारण परेशानी में है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी अनिल गुप्ता ने की तथा प्रदेश नशामुक्त अभियान के प्रभारी हेम राज चौहान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हेमराज चौहान ने बताया कि संस्था के इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग लिया जा रहा है तथा जागरुकता के अलावा प्रभावित लोगों के पुर्नवास आदि में भी संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवा मंडल कोमली बैंक के प्रधान व सचिव लकी, पारुल, महिला मंडल की सदस्यों ने भाग लिया। संस्था ने सड़क पर लोगों को पंपलैट्स बांट कर जागरुक किया।

बस किराया बढ़ाने की निंदा

टीम रीव, शिमला

सरकार द्वारा बसों में किराया वृद्धि और न्यूनतम किराया 6 रुपये करने पर सामाजिक संस्था उद्घोष ने विरोध जताया और इसे मनमानी और बेतुका फरमान करार दिया है। सरकार ने जनता की भावनाओं के विपरीत निर्णय लिया है। संस्था के चेयरमैन हेम राज चौहान ने कहा कि सरकार ने यह जानते हुए भी कि जनता के लिए यह निर्णय हताशा भरा है, केबिनेट ने इस निर्णय पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पलटना होगा तथा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और तुगलकी फरमान से निराशा हाथ लगी है। अब बस में मात्र बैठने के ही 6 रुपये देने होंगे और यात्रा को मंहगा कर सरकार ने दुखती रग पर हाथ रखने जैसा कार्य किया है। बसें हिमाचल जैसे जटिल भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की जीवन रेखा हैं तथा आवाजाही के लिए सबसे उत्तम माध्यम है। विशेषकर गांव में इस सुविधा पर लोगों की निर्भरता है। ऐसे में अब लोगों को एक या दो किलोमीटर तक तो आने–जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि मात्र एक किलोमीटर के लिए 6 रुपये देना ग़रीब जनता पर बोझ से कम नहीं हैं। निजी बस ऑपरेटर्ज सरकारी नियमों को न तो अनुसरण करते हैं और न ही बसों में इस प्रकार की कोई सुविधा है। बस किराया बढ़ा कर लोगों को परेशान करने तक सीमित है। अधिकतर निजि बसों में यात्रियों को टिकट नहीं दिए जाते तथा भेड़–बकरियों की तरह भर कर गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। संस्था सरकार से इस निर्णय पर पुर्नविचार कर इसे वापिस लें अन्यथा 2019 को भी ध्यान में रखें जब प्रताड़ित जनता सरकार से बदला लेगी। संस्था मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर इस निर्णय का विरोध कर रही है।

दरकाली पंचायत में खौफ छोड़ गई बरसात

टीम रीव, शिमला

रामपुर बुशहर की दुर्गम पंचायत दरकाली के दो गांव के लोगों के लिए बरसात अपने पीछे खौफ छोड़ गई है। यहां पर दो गांव में भारी बारिश के बाद गांवों के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। पंचायत के रडोली गांव के ठीक उपर पहाड़ दरक रहा है। साथ ही जमीन लगातार धंस रही है। इतना ही नहीं यहां पर जो प्राकृतिक स्रोत थे वह जमीदोंज हो गए है। हाल ही में आई लगातार बारिश से ये खतरा और बढ़ गया है। अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से बेरहम बारिश हुई तो ये कभी भी इस गांव में तबाही मचा सकती है। ग्रामीण इस दरकते पहाड़ से खौफ के साए में है। पंचायत प्रधान शीरूराम ने मौके का जायजा लेकर इस बारे में राजस्व विभाग को और प्रशासन को दे दी है। गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि रडाली गांव पर मंडरा रहे इस खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाए ताकि कोई अनहोनी न हो। कुछ ऐसा ही खतरा मराला गांव पर ही है। यहां भी भूस्खलन हो रहा है जिसे गांव के लोग दहशत में है। यहां मिट्टी सरकने के बाद पहाड़ दरकने की स्थिति में है।

आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक

चैकअप के साथ स्वास्थ्य परामर्श भी

द रीव टाइम्स, शिमला

ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आईआईआरडी शनान में हाल ही में रीव क्लीनिक खोला गया है। इस क्लीनिक में विभिन्न तरह के टेस्ट कराने की सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य परामर्श भी लोगों को दिया जा रहा है। इस क्लीनिलक से संजौली मल्याना, शनान व पंथाघाटी के आसपास के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। शनान में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर चैकअप करने के लिए भी डीडीयू या संजौली जाना पड़ता था। लेकिन अब शनान में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से काफी आराम है। रीव क्लीनिक के साथ ही यहां पर जनऔषधि केंद्र भी है। इस केंद्र में दवाईयां बाजार से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

बुजुर्गों का सहारा बना मिशन रीव

घर पर ही हो रही स्वास्थ्य जांच

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सोलन में भी स्वास्थ्य स्लेट से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जांच शिविर लगाने के अलावा लोगों के घरों में जाकर भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इससे उन लोगों को काफी आसानी हो रही है जो बीमारी के कारण या बुजुर्ग होने के कारण लंबा सफर तय कर अस्पताल नहीं पहुंच पाते है। घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने से गांव में लोगों को काफी राहत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में जाकर अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मिशन रीव के तहत टेस्ट सुविधा घर पर ही मिल रही है। पहले एक साधारण टेस्ट कराने के लिए निजी क्लीनिक या अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। बसों में भीड़ के बीच बाजार पहुंचना और टेस्ट के लिए लाइनों में लगना और उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार। यह सारी प्रक्रिया मरीज के मर्ज को और बढ़ा देती है। लेकिन मिशन रीव ने इन सारी समस्याओं का हल कर दिया है। स्वास्थ्य सेवक घर में आकर ही टेस्ट सुविधा प्रदान कर रहे हैं , जरूरत पड़ने पर बाजार से दवाईयां लाकर भी घर पहुंचा रहे है।

ऊना में 20 हजार किलो जैविक खाद तैयार

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत प्रदेश के हर जिले में ग्रामीणों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऊना में भी जैविक खाद लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने का जरिया बनता जा रहा है। गगरेट में पिछले दो सप्ताह के भीतर करीब 20 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिसमें 50 से अधिक लोगों को जैविक खाद तैयार करने की विधि बताई गई। अभी तक ऊना में 20 हजार किलो खाद तैयार की गई। उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

- **जैविक खाद के लाभ**
- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।

मिट्टी की दृष्टि से लाभ

- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से

- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

नशे के खिलाफ किया जागरूक

मंदली में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

टीम रीव, ऊना

बंगाणा उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंदली में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग सौ बच्चों समेत उनके अभिभावक व स्कूल स्टाफ सदस्य विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

आईआईआरडी के जिला समन्वयक हनीश शर्मा, बंगाणा खंड समयन्वयक बंदना, बंगाणा खंड के सहायक समन्वय राजिंद्र कुमार और पंचायत फैसिलिटेटर ने सुखदेव ने कार्यक्रम के दौरान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इसके साथ ही मुख्यअतिथि संजीव पराशर ने भी नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया और नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आईआईआरडी का धन्यवाद किया और कहा कि आईआईआरडी की ओर से समाज को नशा मुक्त करने के लिए जो पहल की गई है वह काफी सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में भाषण प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को आईआईआरडी की ओर सर्टीफिकेट प्रदान किए गए।

त्यूरी पंचायत पर टूटा आपदा का कहर बेहाल

रास्ते बंद , बत्ती भी एक सप्ताह तक रही गुल

टीम रीव, ऊना

प्रदेश में आसमान से बरसी आफत की चपेट में ऊना की त्यूरी पंचायत भी आ गई। यहां पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्लखन से न केवल यातायात बाधित हुआ बल्कि लोगों को कई रातें अंधेरे में काटनी पड़ी।

आईआईआरडी के जिला समन्वयक हनीश शर्मा के मुताबिक त्यूरी में करीब एक सप्ताह तक बिजली गुल रही। इसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह लैंड स्लाइड भी लोगों के लिए गले की फांस बन गए । कई जगहों पर अभी भी संपर्क मार्ग टूटे पड़े हैं। स्थानीय लोगों राम किशोर, दौलत राम तरसेम लाल ने बताया कि पंचायत में करीब एक सप्ताह तक बिजली गायब रही। इसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई तो साथ ही नौकरीपेशा लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली न होने से लोग फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते पंचायत से बाहर संपर्क करना भी मुश्किल हो गया था।

गांव के लोगों का कहना है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में मौसम की मार पड़ी है लेकिन फिर भी उनकी पंचायत में बिजली की आपूर्ति को लेकर स्थाई समाधान किया जाना चाहिए। वहीं पंचायत प्रधान प्रमोद कुमार का कहना है कि बारिश से पंचायत में भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए प्रशासन के साथ तालमेल कर रास्तों की बहाली की जा रही है और धीरे–धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है।

स्कूल है पर शिक्षक पूरे नहीं

छोउ भोगर स्कूल में अधर में बच्चों का भविष्य

टीम रीव, सिरमौर

शिक्षा खंड ददाहू तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी धीमान कांप्लेक्स के तहत आने वाला हाई स्कूल छोउ भोगर मात्र एक टीजीटी के हवाले है। यहां 50 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके सभी विषयों को पढ़ाना तथा अन्य कार्य एक मात्र अध्यापक के सहारें है। मई 2016 से स्कूल के स्तरोन्नत होने के बाद दो डेढ़ वर्ष से हाई स्कूल एक मात्र अध्यापक के सहारे चल रहा है, जबकि यहां पांच पद रिक्त चल रहे हैं। आलम यह है कि हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक की पोस्ट खाली है, वहीं टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल टीजीटी, ओटी तथा एलटी की पोस्ट खाली है। हालात यह है कि छोउ भोगर में मात्र एक अध्यापक पिछले डेढ़ वर्ष से 50 से अधिक छात्रों को पढ़ा रहा है।

अभिभावकों का कहना है कि एक अध्यापक के सहारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। कई बच्चों की पढ़ाई अधर में ही छूट रही है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूल में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए। डिप्टी डायरेक्टर उमेश बहुगुणा ने बताया कि स्कूल में फिलहाल एक टीजीटी तैनात है जबकि शास्त्री के आर्डर जारी हो चुके हैं। जल्द ही बाकि तीन पदों पर भी भर्ती कर ली जाएगी। इसके लिए निदेशालय को सूचना भेजी गई है। अब सी एंड वी की अगली सूची निकलते ही पदों की भर्ती कर ली जाएगी।

समस्याओं से जूझ रही नैनीधार पंचायत

टीम रीव, सिरमौर

जिला की नैनीधार पंचायत आज भी विकास को तरस रही है। यहां पीएचसी तो खोल दिया गया लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डाक्टर ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को जरा सी बीमारी के लिए शहर की दौड़ लगानी पड़ती है। यही हाल पंचायत में खुले स्कूल का भी है। स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही पूरे नहीं है। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अभिभावक भी इन व्यवस्थाओं से काफी दुखी है। बार बार आग्रह करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इतना नहीं स्कूल के पर्याप्त जगह भी नहीं है जिसके कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस बारे में भी लंबे समय से अभिभावक प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं लेकिन समस्या का हल होता नहीं दिख रहा है। अभिभावकों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूल को उचित भवन उपलब्ध करवाया जाए और अध्यापकों की भी तैनाती की जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

नैनीधार पंचायत की व्यथा बस इतनी नहीं हैं। इस पंचायत में बने संपर्क मार्ग भी खस्ता हाल है। यह पंचायत आसपास की 11 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। ऐसे में अगर इस पंचायत में बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सके तो आसपास की पंचायतों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत प्रधान अर्चना राणा के मुताबिक नैनीधार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह पंचायत पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है और यहां के

धार्मिक स्थल दोहरा शिवलिंग और चंदपुरधार की सुंदर पहाड़ी काफी लोकप्रिय है। ऐसे में यहां पर अगर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो तो गांव के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा।

नेरीकला में नशे के खिलाफ जागरूकता

टीम रीव, सोलन

प्रदेश में नशे के ख़िलाफ अभियान के तहत सोलन की नेरीकलां पंचायत में आईआईआरडी की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में पूनम ने सहयोग दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया और बताया कि अभिभावक कैसे अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। इस दौरान नेरीकलां पंचायत की महिलाओं ने इस पर न केवल नशे के खिलाफ बात रखी बल्कि लोगों को जागरुक करने के लिए पंपलैटस भी बांटे जिसमें नशे से होने वाले नुकसान और बचाव पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है । कार्यक्रम में कार्यकर्ता पूनम ने बताया कि नशे से जीवन तो विनाश की स्थिति में आ ही जाता है परन्तु सबसे अधिक इसका खामियाजा बच्चों एवं महिलाओं को ही झेलना पड़ता है । इस लिए इस अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है ।

दमील पंचायत में खुले डेयरी

टीम रीव, सोलन

सोलन की दमील पंचायत के लोग आज भी अजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। पंचायत प्रधान लज्या वर्मा का कहना है कि पंचायत में करीब 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही लोग यहां पशुपालन भी करते हैं। दमील पंचायत के हर घर के लोगों ने पशु खासकर गाय पाल रखी है। ऐसे में पंचायत में अच्छा खासा दुग्ध उत्पादन होता है। लेकिन दूध बेचने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है। पंचायत से शहर जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में आय–व्यय बराबर हो जाता है। लोगों को दूध उत्पादन से सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में एक डेयरी खोली जानी चाहिए ताकि पंचायत के लोगों को स्वरोजगार मिले और लोगों को दूध उत्पादन के सही दाम मिल सके।

ग्रामीणों ने उठाई मांग

पंचायत में युवा आबादी भी काफी है। अगर डेयरी खुलती है तो युवाओं का रूझान भी पशुपालन की तरफ होगा और उन्हें रोजगार की तलाश में इधर–उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

द रीव टाइम्स की टीम ने जब पंचायत प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि पंचायत में डेयरी खोली जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मिशन रीव के तहत गांव में दी जा रही सेवाओं की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि मिशन रीव के तहत पशुपालकों को उपल्बध करवाया जा रहा फीड सप्लीमेंट काफी फायदेमंद साबित हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम

घर पर ही बन रहे लोगों के स्वास्थ्य कार्ड

सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहा मिशन रीव

ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते मिशन रीव के सदस्य

टीम रीव, कांगड़ा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने स्तर पर सेवाएं देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव बेहतरीन कार्य कर रहा है। अपने इसी प्रयास के तहत कांगड़ा जिला में मिशन रीव के तहत ढाई सौ से अधिक हैल्थ कार्ड बनवाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

गांव में ही इस सुविधा के मिलने के बाद लोगों ने भी मिशन रीव की काफी सराहना की। लंबागांव ब्लॉक के जोडबर गांव की रक्षा देवी ने का कहना है कि पहले हैल्थकार्ड बनाने के लिए धर्मशाला जाना पड़ता था लेकिन अब मिशन रीव के तहत घर पर ही हैल्थ कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की गई जिससे

घर पर ही मिल रही स्वास्थ्य कार्ड बनाने की सुविधा

काफी सुविधा हुई है। इसी तरह पंचरूखी ब्लॉक के छेब गांव की निर्मला देवी ने बताया कि पहले एक हैल्थ कार्ड बनवाने के लिए कंप्यूटर सेंटर के 10 चक्कर काटने पड़ते थे या कार्ड बनवाने के लिए पूरे परिवार को लेकर धर्मशाला जाना पड़ता था। लेकिन अब मिशन रीव के तहत घर पर ही यह सुविधा मिल रही है।

स्वास्थ्य कार्ड इसलिए जरूरी

बीते वर्ष ही यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम में उन लोगों को कवर किया जा रहा है, जो न तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आते हैं और न ही मुख्यमंत्री स्टेट हैल्थ केयर स्कीम में। ऐसे लोगों के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। इसमें एक दिन के एक रुपए (साल के 365 रुपए) में मरीज को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हैल्थ कार्ड बनाना जरूरी है। यह कार्ड एक साल, दो साल और तीन साल के लिए बनता है। हालांकि एक साल से ज्यादा अवधि के लिए कार्ड बनाने पर कुछ रियायत भी दी जा रही है। इससे उस वर्ग के तबके को काफी बड़ी राहत है जो सरकार की किसी भी स्वास्थ्य योजना में नहीं आते हैं। योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कार्ड बनाते समय में मरीज की पहले की स्थिति भी कवर की जाती है। यह सुविधा बहुत सी हैल्थ पालिसी में नहीं होती है। स्वास्थ्य योजना में सामान्य परिस्थितियों और क्रिटिकल केयर में यात्रा का खर्च देने का भी प्रावधान है।

ये हैं फायदे

- 30 हजार रुपए तक का कैशलैस इलाज
- गंभीर बीमारी पर 1.75 लाख तक की ट्रीटमेंट
- कैंसर पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर पर 2. 25 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा

हमीरपुर में नशे के खिलाफ एकजुट हुए लोग

विभिन्न स्थानों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन

टीम रीव, हमीरपुर

आईआईआरडी की ओर से बीते पांच सितंबर को प्रदेश में शुरू की किए गए अभियान को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रह है। हमीरपुर में आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी इसी अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में बड़सर के विधायक लखनपाल से आईआईआरडी के अधिकारियों ने मुलाकात की और उन्हें संस्था की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें नशा मुक्त हिमाचल अभियान के बारे में भी बताया गया। विधायक ने इस अभियान की जमकर प्रशंसा की और कहा कि जागरुकता से ही समाज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर किया जा सकता है।

इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों में 'जिंदगी जियें नशें को नहीं' थीम पर भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनबीपीएस स्कूल बिजड़ी और नवभारत स्कूल कोटला में भी इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेताओं को आईआईआरडी की ओर से सर्टीफिकेट भी प्रदान किए गए। स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों ने आईआईआरडी के इस नशामुक्त अभियान को सामाजिक सरोकार से जुड़ा बताया और कहा कि संस्था की ओर से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

शाम को बस चलाने की मांग

बस सर्विस न होने से लोग परेशान

टीम रीव, हमीरपुर

नड़ियाणा–सड़ियाणा वाया सेंट्रल स्कूल होकर बल्ह, अमरोह व मझोग सहित करीब 20 गांव बस सुविधा के लिए तरस रहे हैं। शाम चार बजे के बाद इस रूट पर कोई बस सेवा नहीं है। महीनों पहले चलने वाली एक निजी बस भी किन्हीं कारणों से बंद हो गई है। अब हालात ऐसे हैं कि अगर कहीं से वापस घर लौटना है तो चार बजे से पहले ही लौटना पड़ता है। इसके बाद मुसीबत बढ़ जाती है। न तो यहां से जाने के लिए बस मिलेगी और न ही कहीं से आते समय। ऐसे में ग्रामीण खासे परेशान हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस बारे क्षेत्रीय परिवहन विभाग को भी अवगत करवाया जा चुका है। लोगों ने बताया कि 20 गांवों के लिए चार बजे के बाद बस सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों ने आरटीओ से बस चलाने की मांग की थी। बस चलाने के संदर्भ में आरटीओ ने निगम प्रबंधन को लिखा था। छह माह बीत जाने के उपरांत भी निगम ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं कर पाया है। पिछले छह महीने पहले एक निजी बस इस रूट पर चलती थी। इस बस को किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया। उसके बाद अभी तक इस रूट पर कोई बस नहीं चलाई गई है। इस क्षेत्र के लोगों ने भी निगम प्रबंधन से इस रूट पर बस चलाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि वे कई बार इस रास्ते पर मुंह के बल गिर चुके हैं और बुरी तरह घायल हो चुके हैं।

पंचायत फेसीलिटेटर को दिया प्रशिक्षण

टीम रीव, कांगड़ा

आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत विभिन्न पंचायतों में लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए खासतौर पर पंचायत फेसिलिटेटर की नियुक्ति की गई है। इन पंचायत फेसिलिटेटर को क्षमता संवर्द्धन के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिला कांगड़ा में पंचायत फेसिलिटेटर के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य स्लेट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आईआईआरडी कार्यालय शिमला से आए प्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी पीएफ को दी। इसके साथ ही उन्हें पीओएस मशीनों के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।

मिशन रीव ने खोले रोजगार के द्वार

अपनी ही पंचायत में काम करने का मिला मौका

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है। ज़िले के अभी तक करीब सैकड़ों ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रकिया जारी है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे किसानों ने रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में फेसिलिटेटर पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा

ऑनलाइन सिस्टम भी जान रहे ग्रामीण पंचायत में ही रोजगार से खुशी

किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है।

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। लोगों को उनके घरों में ही टेस्ट सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से मिलने से ग्रामीण काफी खुश है।

जान जोखिम में डाल चल रही जिंदगी

सड़क सुविधा के लिए तरस रहे धार धंगड़ के लोग

टीम रीव, कांगड़ा

देहरा विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में बसने वाले धार धंगड़ लुणसू के लोगों का जीवन आज भी मुश्किलों मे कट रहा है। यह क्षेत्र अभी भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। यहां ट्रेन ही लोगों की जिंदगी को आगे ले जाने का एकमात्र सहारा है लेकिन यह भी पिछले तीन माह से बंद पड़ी है। हालात ये है कि स्कूली बच्चे रेलवे पुलों से होकर खौफनाक सफर करके स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों ने बताया कि वह पांच किलोमीटर रेलवे लाइन से होकर खतरनाक पुलों को क्रॉस करते हुए स्कूल पहुंचते है। उनका पूरा दिन पैदल सफर में ही निकल जाता है। सुबह पांच बजे उठते हैं, तब कहीं जाकर समय पर स्कूल पहुंच पाते हैं। बीमारी की स्थिति में हालत और भी मुश्किल हो जाते हैं। पहले मरीज को मीलों पैदल कंधे पर उठाकर या फिर पालकी के सहारे पहले मेन सड़क तक पहुंचाया जाता है या फिर कहीं जाकर अस्पताल पहुंच पाते हैं। गौरतलब है की धार पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इन गांवों में सड़क न होने तथा ट्रेनें बंद होने के मामले को जनमंच कार्यक्रम में कई बार उठाया लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। यहां के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि समस्या का निवारण किया जाए।

मिशन रीव ने रजनीश का सपना किया साकार

ग्रामीण युवाओं के लिए बन रहे प्रेरणा स्त्रोत

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर में बतौर स्वास्थ्य सेवक काम कर रहे रजनीश भारद्वाज अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। मिशन रीव के तहत रजनीश न केवल पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं बल्कि मिशन रीव की अन्य सेवाएं भी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। हमीरपुर में सुजानपुर ब्लॉक की सपाहल पंचायत से संबंध रखने वाल रजनीश बद्दी में एक निजी कंपनी में काम करते थे। घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें घर से दूर जाने के लिए मजबूर कर रखा था। रजनीश का कहना है कि जब वह बद्दी में काम करते थे तो हमेशा यही सोचते थे कि काश! कोई उन्हें अपनी पंचायत, अपने घर में ही काम करने का मौका देता ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर पाते और पंचायत के लोगों की भी सेवा कर पाते। रजनीश के इस सपने को पूरा किया मिशन रीव ने। इसके बाद एक जनवरी 2018 को ही रजनीश ने मिशन रीव में बतौर पंचायत फेसिलिटेटर ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने आईआईआरडी से स्वास्थ्य स्लेट समेत विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब वह अपनी पंचायत के अलावा साथ लगती पंचायत में भी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाने के साथ ही लोगों के घरों में भी रजनीश सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें मिशन रीव की जानकारी भी दे रहे हैं।

गांव में सुधरे सड़कों का सुधार

कृषि में सुधार के लिए भी उठाए कदम

टीम रीव, बिलासपुर

बिलासपुर की दाबला पंचायत में लोग काफी समय से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे है। पंचायत प्रधान चिंत राम ने बताया कि दाबला में बस सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने संबंधित विभाग से गुहार लगाई है कि उनकी पंचायत के लिए बस लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। टीम रीव, बिलासपुर दाबला पंचायत के लोगों ने सरकार से मांग की है कि उनके पंचायत में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। दाबला पंचायत के प्रधान चिंत राम ने बताया कि पंचायत इसके साथ ही बेहतर किस्म के बीज उपलब्ध करवाना डंगे बनाना ,सोलर लाइट की सुविधाएं उपलब्ध करवाना कुछ ऐसी मांगे हैं जो दाबला पंचायत के लोग सरकार के

सामने उठाना चाहते है। लोगों का कहना है कि पंचायत में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे पंचायत का विकास हो सके और गांव के लोगों खासकर युवाओं को गांव में ही स्वरोजगार मिल सकें। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है।

प्रधान चिंत राम ने कहा कि उन्हें मिशन रीव से काफी उम्मीदे हैं क्योंकि मिशन रीव के तहत विभिन्न सुविधाएं गांव में लोगों के घर पर ही दी जा रही है। इसके लिए मिशन रीव की प्रशंसा की।

जोखिम में जान डाल रहे बच्चे

टीम रीव, हमीरपुर

नगर पंचायत भोटा वार्ड नंबर सात में स्कूल जाने वाला रास्ता खस्ताहाल है। बच्चे रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाते हैं। जरा सी भी चूक बड़े हादसे में तबदील हो सकती है।

वहीं कुछ साल पहले इस रास्ते के लिए पुलिया का निर्माण शुरू हुआ, वह भी अभी अधर में ही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बारिश होते ही सड़क लोगो के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। स्कूल के बच्चे व अध्यापक अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते हैं। फौरी तौर पर स्थानीय लोगों ने नाले के ऊपर दो बिजली के पोल बिछा दिए। पोल डालकर स्कूल के बच्चों के लिए रास्ता बनाया गया है।

लोगों का यह भी कहना है कि वे कई बार इस रास्ते पर मुंह के बल गिर चुके हैं और बुरी तरह घायल हो चुके हैं।

भुंतर में जल्द खुलेगा जनऔषधि केंद्र

टीम रीव, कुल्लू

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत कुल्लू में भुंतर के हाथीथान में भी लोगों को जल्द ही जनऔषधि केंद्र खोला जाएगा। भुंतर में यह पहला जनआषधि केंद्र होगा। इसके खुलने से भुंतर के लोगों को अब सस्ती दवाईयों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तहत हाथीथान में सस्ती दवाईयां उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज सस्ता होगा और लोगों के समय की भी बचत भी होगी।

उल्लेखनीय है प्रदेश के लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच जनऔषधी केन्द्रों का लोकार्पण तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और वर्तमान मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश बीके अग्रवाल ने रीव सचिवालय शिमला से किया था।

भुंतर निवासी सुमेर का कहना है कि अभी तक उन्हें बाजार से मंहगे दामों पर दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। कई बार तो ये दवाईयां जेब पर इतनी भारी पड़ जाती थी कि घर का पूरा बजट ही बिगड़ जाता था। लेकिन अब आईआईआरडी की ओर से प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के

उन्होंने इस दौरान कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और लोगों को इसकी रक्षा के लिए मंहगी दवाईयों के लिए अब नहीं तड़पना पड़ेगा तथा जनाऔषधी केन्द्रों से अब सभी को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता होगी ।

ये होगी सुविधा आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध होगी। इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए शहरों में भटकना पड़ता था। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में तीन सौ जनऔषधि चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

चम्बा में तबाही का मंजर

टीम रीव, चम्बा

जिला चम्बा में मौसम ने भारी तबाही मचाई है। इस बार बरसात चंबा को गहरे जख्म दे गई है। बरसात से पूरे जिले में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। चम्बा से भरमौर मार्ग हर जगह क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा।। जिला चम्बा के मुख्य कार्यालय के साथ लगते प्राचीन शीतला पुल को भारी क्षती पहुंची है। इस पुल के साथ लगते मोहल्ले को दो रात तक दूसरो के घरों में शरण लेनी पड़ी। पंचायत होली में बादल फटने के कारण कई घरों में दरारे आई और फसल पानी में बह गई है। जिला चम्बा का एन. एच. मार्ग पठानकोट से चम्बा तक जगह–जगह पहाड़ी खिसकने से मार्ग दो दिन तक यातायात के लिए बन्द रहा । इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लॉक पांगी में हिमपात होने के कारण कई दिनों तक निजी गाड़ियां फंसी रही। ब्लॉक सलूणी और तीसा में जगह–जगह पहाड़ी खिसकने के कारण यातायात सुविधा कई दिनों तक बहाल नहीं हो पाई है। अभी तक एचआरटीसी की कई फंसी हुई है।

स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है जो लोग भारी बरसात के कारण बेघर हो गए हैं उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जानी चाहिए ताकि वह जीवन यापन कर सके।

FLYERS GROUP PRIVATE LIMITED

PRODUCTS		FGPL RATE	MARKET RATE
HOUSEHOLD KITCHEN WARE (Microwave Safe, Food Grade Containers)			
Full Plate 26.5 cm (6 Pcs Set)		290.00	350.00
Full Plate 28 cm (6 Pcs Set)		330.00	400.00
Glass 350 ml (6 Pcs Set)		180.00	200.00
Cook & Serve 1800ml (Two Partition)		130.00	250.00
Cook & Serve 1800 ml (Three Partition)		150.00	230.00
Dinner Set (32 Pcs)		1200.00	1750.00
Lunch Box (3 Pcs of 300ml) with cover		250.00	320.00
Unbreakable Polycarbonate Glass(6 Pcs Set) (Big) - 400ml		300.00	400.00
Kitchen Containers (3 Pcs Set)		950.00	1250.00
Folding (Fruit and Vegetable) Basket		230.00	410.00
Masala Box (7 Compartments with one Spoon)		230.00	300.00
HOUSEHOLD CONSUMABLES			
Neem Soap	100 gm	10.00	15.00
Glycerin Soap	125 gm	15.00	35.00
Bathing Soap	100 gm	15.00	25.00
Antiseptic Soap	125 gm	14.00	40.00
Fruit Soap	135 gm	11.00	30.00
Coconut Based Detergent Soap	250 gm	10.00	15.00
2 Gotti Detergent Powder	100 gm	9.00	10.00
3 Patti Detergent Powder	1 kg	58.00	75.00
Omay Detergent Powder	1 kg	46.00	60.00
Ujala Detergent Powder	1 kg	46.00	60.00
Kitty Detergent Powder	1 kg	58.00	75.00
Utensil Soap Bar	500 gm	45.00	50.00
Toilet Cleaner (blue)	1 ltr	65.00	75.00
Bathroom Tile Cleaner	1 ltr	75.00	85.00
Liquid Dish Washer	500 ml	65.00	70.00
Liquid Dish Washer	250 ml	45.00	50.00
Hair Oil Sachets	2 ml	1.00	1.00
Rosa Shampoo Sachets	8 ml	1.00	1.00
Tooth Brush (Medium)	1 unit	12.00	20.00
Tooth Paste	27 gm	10.00	15.00
Super White Detergent Powder (Washing Machine)	4 kg	320.00	375.00
Fine Detergent Powder	4 kg	415.00	440.00
Polo Air Freshner	12 pcs	300.00	450.00
Starglow No.1 Bathing Soap	100 gm	25.00	30.00
Jo Soap	30 gm	8.00	10.00
Neha Herbal Mehandi	140 gm	45.00	50.00
Duke Neem Soap	1 pcs	23.00	25.00
Almond Olive Hair Oil	200 ml	121.00	130.00
Scrubber	1 pcs	8.00	10.00
Paper Soap Strips	10 strips	19.00	20.00
Amla Hair Oil	200 ml	75.00	110.00
Anti Dandruff Shampoo	500 ml	175.00	200.00
Neha Herbal Mehandi Cone	12 pcs	60.00	120.00
Green Apple Shampoo	500 ml	140.00	160.00
Herbal Shampoo (Shikakai & Amla)	500 ml	140.00	160.00
Hair Oil (Bhringraj Chameli & Rambha)	200 ml	75.00	90.00
Disinfectent Surface Cleaner	1 ltr	140.00	150.00
Liquid Wool Fabric Detergent	500 ml	84.00	90.00
Coconut Hair Oil	200 ml	71.00	80.00
Floor Cleaner Sanitizer	200 ml	95.00	110.00
Sanitary Napkins	1 Packet (set of 7 pads)	25.00	35.00
LED Television (INCL GST) + 1 Year Warranty			
LED HD Television 24”		8200.00	11200.00
LED HD Television 32”		11000.00	15000.00
LED HD Smart Television 32”		13500.00	16000.00
LED HD Television 40”		15000.00	19500.00
LED HD Smart Television 40”		18000.00	22000.00
LED HD Smart Television 50”		32900.00	42000.00

For queries Contact : +91-94595 84566, +91-82191 75636
Flyers Group Private Limited, IIRD Complex, Byepass Road, Shanan, Shimla, Himachal Pradesh - 171006

चंबा मे चित्रों से नशा निवारण का संदेश

टीम रीव, चंबा

जिला चम्बा द्वारा संचालित मिशन रीव के तहत "जिंदगी जियें –नशे को नहीं " प्रदेशव्यापी नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत ,राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाषण व् चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमे सलूणी ,मेहला ,तीसा , चम्बा उपमंडल के विभिन्न स्कूलों (यश पब्लिक स्कूल उदयपुर ,राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भलेई ,राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाट और गुरुकुल पब्लिक स्कूल लचोड़ी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल उदयपुर) से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलेई की छात्रा प्रियांशु व् गुरुकुल पब्लिक स्कूल लाचोड़ी की छात्रा मिनालिनी ने प्रथम स्थान हासिल किया व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलेई की ज्योति ठाकुर ने द्वितीय स्थान हासिल किया और सेजल कुमारी गुरुकुल पब्लिक स्कूल लचोड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया और चित्रकला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्र चिन्मया ने प्रथम, कृतिका ने दूसरा व हिमानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि शिव पब्लिक स्कूल चैनेड के चेयरमैन मंजीत सिंह ठाकुर (भनौता) रहे। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर के प्रधानाचार्य व सम्पूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। मिशन रीव की ओर से राकेश शर्मा जिला समन्वयक ,विकास शर्मा अतिरिक्त जिला समन्वयक ,तथा अतिरिक्त खंड समन्वयक नितेश ठाकुर ,रविंदर ठाकुर, गोविन्द ठाकुर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया जो आईआईआरडी कार्यालय शिमला में आयोजित की गई।

ग्राम सभा में लोगों को किया जागरूक

टीम रीव, मण्डी

मण्डी की विभिन्न पंचायतों में मिशन रीव और अन्य विकासात्मक योजनाओं के बारे में लोगों को ग्रामसभा के दौरान जागरूक किया गया। ग्राम सभा के दौरान लोगों को बताया गया कि कैसे मिशन रीव के तहत विभिन्न तरह की सेवाएं गांव में लोगों को दी जा रही है। मिशन रीव के तहत ग्रामीणों के रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति भी घर पर की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य जांच और बेहतर कृषि पैदावार के लिए जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत जिला मण्डी में अभी तक सैंकड़ो किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण के अलावा किसानों की खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवाओं के अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी भी ग्रामसभा के दौरान लोगों को दी गई।

तीसा में लोगों का स्वास्थ्य जांचा

टीम रीव, चम्बा

चंबा के ब्लॉक तीसा के गांव डोंरी पंचायत भूंजरारू में स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य सेवक केवल शर्मा और पंचायत पीएफ जयबंती की देख रेख में किया गया ।इस शिविर में लोगों ने शुगर, एचबी, ब्लड प्रेशर ,पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट करवाए। इस दौरान विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बारे में भी लोगो को जागरूक किया। लोगों को घर–घर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत करवाया गया ।

शिविर के दौरान जनऔषधि केंद्र से दवाईयां भी मरीजों को मुहैया करवाई गई । मिशन रीव के तहत दी जा रही इन सुविधाओं से ग्रामीण काफी खुश हैं। तीसा की तरह जिला चंबा में अन्य स्थानों पर भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से लोगों के घरों पर ही उनके प्रारंभिक टेस्ट किए जा रहे हैं।

आओ कानून को जानें

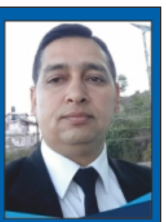

कानूनी सहायता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया । इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया । इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है । साथ ही, इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं ।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। इनका काम प्राधिकरण की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों की अध्यक्षता संबंधित जिले के मुख्य न्यायाधीश और तालुका कानूनी सेवा समितियों की अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य

प्राधिकरण देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीमें लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है ।

मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहयता समितियों आदि को निम्नलिखित कार्य नियमित आधार पर करते रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

- सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना
- विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना

- **मुफ्त कानूनी सेवाएं**
- किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रभार अदा करना,
- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना,
- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना,
- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र

- महिलाएं और बच्चे
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक श्रमिक
- बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में रखे गए लोग
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार
-

प्राधिकरण की योजनाएं

- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्राधिकरण ने निम्नलिखित स्कीमें बनाई हैं:

कानूनी सहायता स्कीम

प्राधिकरण ने ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता वकील योजना के तहत सहायता देनी शुरू की जो संसाधनों के अभाव अथवा विकलांगता के कारण अपना बचाव नहीं कर सकते और अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं रख सकते । अब हर मजिस्ट्रेट की अदालत के साथ कानूनी सहायता वकील लगाए गए हैं जो पुलिस द्वारा पेश किए जाने के दिन से ही, वकील न रख पाने वालों का बचाव करते हैं।

स्थायी और निरंतर लोक अदालत स्कीम

अधिनियम की धारा 19 के तहत देश के सभी जिलों में लोक अदालतें स्थापित करने के लिए एक स्थायी और निरंतर लोक अदालत स्कीम लागू की गई है । इसके तहत अदालत परिसर से दूर निर्धारित स्थानों पर अब तक लोक अदालतें आयोजित होती हैं और जो मामले इनमें नहीं सुलझ पाते, वे अगली लोक अदालतों में ले जाए जाते हैं । इस प्रकार ये अदालतें निरंतर लगती हैं ।

सलाह और समाधान स्कीम

प्राधिकरण ने एक सलाह और समाधान स्कीम तैयार की है जिसके तहत बातचीत और सुलह सफाई के जरिए मामले निपटाए जाएंगे । इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में न्यायार्थियों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले सुलझाने के लिए समझाया जाएगा । अधिसंख्य जिलों में इस प्रकार के केंद्र खोले जा चुके हैं ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे । प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का छठा अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का कमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

कौन हैं हमारे दिव्य पितर, जानिए रहस्य

धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उर्ध्वभाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है।

यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडनल, सोम, अर्यमा और यम– ये चार इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश ।

इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा– अग्निष्व, देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा–साध्यों के प्रतिनिधि तथा बर्हिपद–गंधर्व, राक्षस, किन्नर सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं । इन सबसे गठित जो जमात है, वही पितर हैं । यही मृत्यु के बाद न्याय करती है । भगवान चित्रगुप्तजी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल हैं । ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है ।

'पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है । पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है– दिव्य पितर और मनुष्य पितर । दिव्य पितर उस जमात का नाम है, जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए, इसका निर्णय करता है । इस जमात का प्रधान यमराज है ।

दिव्य पितर की जमात के सदस्यगण : अग्निष्वात्त, बर्हिपद आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयन्तुन, श्राद्धभुक व नान्दीमुख ये नौ दिव्य पितर बताए गए हैं । आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं ।

अर्यमा का परिचय : आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण (अर्यमा) और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है । पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा । अर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा–फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है।

इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है जड़–चेतन मयी सृष्टि में, शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है । श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र (सूर्य) तथा वरुण (जल) देवता के साथ स्वाहा का 'हव्य' और श्राद्ध में स्वधा का 'कव्य' दोनों स्वीकार करते हैं ।

श्राद्ध पक्ष में कैसे पहुंचता है पितरों को भोजन

पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है । एक लाख योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है ।

कैसे नीचे आते हैं पितर?

'सूर्य की सहस्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम 'अमा' है । उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं । उसी अमा में तिथि विशेष को वस्य अर्थात चन्द्र का भ्रमण होता है तब उक्त किरण के माध्यम से चन्द्रमा के उर्ध्वभाग से पितर धरती पर उतर आते हैं ।

'इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है । अमावस्या के साथ मन्वादि तिथि, संक्रांतिकाल व्यतिपात, गजच्दाया, चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण इन समस्त तिथि–वारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है ।

ऊपर कैसे पहुंचता है भोजन?

'जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा ।

'देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग–अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाती है।

'एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है । उसी पर विशेष अन्न अर्पित किया जाता है । तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है।

' पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा–अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुंचते हैं।

' मृत्युलोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है, जो पितृलोक की यात्रा पर हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहां कहीं भी उनकी स्थिति हो, जाकर तृप्त करते हैं।

' अतः श्राद्धपक्ष में पितरों का पिंडदान और तर्पण कर अपनों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं।

जानिए किस तिथि को कौन सा श्राद्ध आएगा

24 सितंबर 2018 पूर्णिमा श्राद्ध	2 अक्टूबर 2018 अष्टमी श्राद्ध
25 सितंबर 2018 प्रतिपदा श्राद्ध	3 अक्टूबर 2018 नवमी श्राद्ध
26 सितंबर 2018 द्वितीय श्राद्ध	4 अक्टूबर 2018 दशमी श्राद्ध
27 सितंबर 2018 तृतिया श्राद्ध	5 अक्टूबर 2018 एकादशी श्राद्ध
28 सितंबर 2018 चतुर्थी श्राद्ध	6 अक्टूबर 2018 द्वादशी श्राद्ध
29 सितंबर 2018 पंचमी श्राद्ध	7 अक्टूबर 2018 त्रयोदशी श्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध
30 सितंबर 2018 षष्ठी श्राद्ध	
1 अक्टूबर 2018 सप्तमी श्राद्ध	8 अक्टूबर 2018 सर्वपितृ अमावस्या

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

ब्लड प्रेशर : कारण एवं निदान

रक्तचाप धमनियों द्वारा बहने वाले खून से धमनियों की दीवारों पर लगाए गए बल की मात्रा है । उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्शन) को धमनियों में उच्च दबाव (तनाव) के रूप में जाना जाता है। रक्तचाप 2 तरीके से मापा जाता है । सिस्टल रक्तचाप हृदय के संकुचन के दौरान धमनियों में दबाव के बराबर होता है। डायस्टोलिक दबाव दिल की छूट के दौरान धमनियों में दबाव है । वे दोनों पारे के मिलीमीटर (एम.एम.एच.जी) में मापे जाते है।

जिस व्यक्ति का रक्तचाप लगातार 140/90 एम.एम.एच.जी या उससे अधिक, हो वह हाइपरटेन्शन से पीड़ित है । रक्तचाप आमतौर पर पांच श्रेणियों में बांटा जाता है:

1. हाइपोटेंशन (कम रक्तचाप)
– सिस्टोलिक एम.एम.एच.जी 90 या उससे कम, या
– डायस्टोलिक एम.एम.एच.जी 60 या उससे कम

2. साधारण
– सिस्टोलिक एम.एम.एच.जी 90–119, और
– डायस्टोलिक एम.एम.एच.जी 60–79

3. प्रीहाइपरटेन्शन
– सिस्टोलिक एम.एम.एच.जी 120–139, या
– डायस्टोलिक एम.एम.एच.जी 80–8 9

4. चरण 1 उच्च रक्तचाप
– सिस्टोलिक एम.एम.एच.जी 140–159, या
– डायस्टोलिक एम.एम.एच.जी 90– 99

5. चरण 2 उच्च रक्तचाप
– 160 से अधिक सिस्टोलिक एम.एम.एच.जी, या
– डायस्टोलिक एम.एम.एच.जी 100 से अधिक

यदि आपको उच्च रक्तचाप है, तो यह उच्च दबाव आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त तनाव डालता है। समय के साथ, यह अतिरिक्त तनाव आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप की जटिलताओं में हृदय रोग, गुर्दा (गुर्दे) रोग, धमनियों का सख्त होना, आंखों की क्षति, और स्ट्रोक (मस्तिष्क क्षति) शामिल है।

उच्च रक्तचाप के लक्षण

उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक कि स्तर 180/110 एम.एम.एच.जी तक उच्च नहीं हो जाता । हालांकि, यदि उपचार न किया जाए, तो यह गंभीर समस्याओं जैसे कि दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा देता है।

उच्च रक्तचाप के लक्षणों में शामिल हैं:

सिरदर्द, आमतौर पर कई दिनों तक टिकाऊ
मतली – उल्टी की आग्रह के साथ पेट में अस्वस्थता और असुविधा का ख्याल
उल्टी चक्कर आना – हल्कापन, अस्थिरता और सिर का चक्कर
धुंधली या द्विगुण दृष्टि (डिप्लोपिआ)
नकसीर फूटना (एपिस्टेक्सिस) – नाक से खून आना
घबराहट डिस्पेनिया – श्वास कष्ट

यदि लंबे समय तक बिना–इलाज छोड़ा जाता है, तो उच्च रक्तचाप इन जटिलताओं को जन्म दे सकता है:

दिल का दौरा, स्ट्रोक, हृदपात (हृदय का रुक जाना)
धमनीविस्फार
खून के थक्के
गुर्दा रोग और गुर्दा की विफलता
पाचन किया में दिक्कत आदि लक्षण
स्मृति/स्मरण की समस्या

विभिन्न स्थितियों और दवाओं से उच्च रक्तचाप हो सकता है, जिनमें शामिल हैं:

नींद की समस्या, गुर्दे से संबंधित समस्याएं, थायरॉयड समस्याएं
रक्त वाहिकाओं में कुछ दोष जिसके साथ आप जन्म लेते हैं (जन्मजात) कुछ दवाएं, जैसे जन्म नियंत्रण की गोलियां, ठंड के उपचार, दर्द निवारक और कुछ निर्धारित दवाओं का सेवन
अवैध दवाएं, जैसे कोकीन और एम्फेटामीन्स का सेवन
शराब का दुरुपयोग या शराब का चिरकालिक उपयोग

इसके अलावा, आप उच्च रक्तचाप के बढ़ते जोखिम पर हैं, यदि आप:
65 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।
अफ्रीकी या कैरिबियाई मूल के हैं ।
आपका कोई रिश्तेदार, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।
बहुत ज्यादा नमक खाते हैं और पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं खाते हैं। पर्याप्त व्यायाम नही करते हैं।
बहुत अधिक शराब या कॉफी पीते हैं (या अन्य कैफीन आधारित पेय)। धूम्रपान करते हैं। पर्याप्त नींद नहीं मिलती है।

उपचार

डॉक्टर से चेकअप करवाएं
वांछित टैस्ट करवाएं
डॉक्टर की सलाह से ही दवाईयों का नियमित सेवन करें

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:
therievtime@iirdshimla.org

परंपराओं की आड़ में विवेक की तिलांजलि

इतिहास कहता है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारों तलहटियों तथा मैदानी क्षेत्रों से आरम्भ हुआ। युद्ध के भय, अन्वेशण की चाह तथा एकाकी जीवन जीने आदि कारणों से एक बड़ी जन संख्या दूर दराज़ पहाड़ों की ओर जाकर बसने लगी। पहाड़ो के विस्तार तथा खुलेपन के होते हुए लोगों का बिखराव हुआ तथा कालान्तर में परिवार बड़े कुटुम्ब में तथा कुटुम्ब गांव में परिवर्तित होने लगे। क्योंकि पहाड़ों में बिखरे रूप मे बसने वाले लोगों का मैदानी क्षेत्रों में अधिक सामूहिक रूप से रहने वाली जनसंख्या में संचार साधन न होने के कारण, दूर–दूर तक कोई नाता नही रहा, जो वैचारिक उन्नति समूहों में रहने वाले मैदानी क्षेत्रों में हुई, वह पहाड़ों तक न पहुंच पाई। पहाड़ी कबीलों में शक्तिशाली व बलशाली रसूखदारों ने बहुत सारी मनगढ़ंत जीवनशैली को बढ़ावा दिया तथा कालान्तर में जो जीवन दर्शन से जुड़ी रचनाऐं भी मानव समाज को मिली। उनका भी सही से व्याख्यान न होने के कारण कई प्रकार की रुढ़ियों ने जन्म लिया जिनका मानव प्रगति से दूर–दूर तक कोई नाता नहीं। यही कारण है कि जैसे–जैसे हम दूर तक पहाड़ों की जीवन शैली देखते हैं, वैसे–वैसे तामसिक वृत्तियों का वर्चस्व अधिक दिखाई देने लगता है। जैसे कि काल्पनिक दैव्यों की पूजा, मंदिरों में लकड़ी व पत्थर की मूर्त को देवता बनाना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना, जीवन के दुःखों के निवारण तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तिल–जौ लेकर हवन करना आदि–आदि ऐसे ही ढेर सारी रुढ़ियां शिक्षा से अछूत मैदानी क्षेत्र में पनपी जिन्हें अब शिक्षित समाज भी जूझ रहा है। यह हमारी शिक्षा का पंगु होना दर्शाता है कि हम डिग्रियां लेकर भी समाज की रुढ़ियों जो कि हमें पीछे धकेल रही है, पर विवेकपूर्वक चर्चा करने से कतराते हैं। जहां शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की चिंतन शक्तियों को दीवारहीन बनाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए अनुकूल बनाता है। वहीं हम परंपराओं तथा रुढ़ियों की कुछ ऐसी दीवारें बना बैठे हैं कि उन्हें दूर करना तो क्या, पर हम उन पर चर्चा करना भी अपराध समझते हैं। सदियों से आ रही इन रुढ़ियों पर समय–समय पर कई महान आत्माओं ने कुठाराघात करने के प्रयास भी किए लेकिन इनकी आधारशिला इतनी सशक्त है कि उनके सभी प्रयास बहुत तीव्रता से प्रभाव न छोड़ सके। लगभग 7000 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद् गीता द्वारा इन समस्त रुढ़ियों का खण्डन किया परन्तु इनका सही भाव आज तक आम इन्सानों की पंहुच से दूर ही है। गीता ज्ञान को आज भी लोग पांडवों–कौरवों के मध्य के शस्त्र युद्ध के संदर्भ में देखते हैं जबकि गीता में कभी शस्त्रयुद्ध की बात नहीं की गई है। श्रीकृष्ण के बाद जीजस क्राइस्ट, गैलिलियो, सुकरात, दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने मनुष्य जाति को सत्य से आत्मसात करने का प्रयास किया। लेकिन सभी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में सदी के महान चिंतक प्रोफेसर राम कुमार गुप्ता की टिप्पणी में किसी पाश्चात्य लेखक, वैचारक का उल्लेख याद आता है कि यदि आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो इसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हो जाओ। प्रश्न यह है कि आख़िर हमने पिछले लगभग 10000 वर्षों से सीख क्या ली है? आख़िर क्यों हम उसी मार्ग पर अग्रसर हैं जिसका कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है अपितु भटकाव ही भटकाव है। विडंबना तो यह है कि न केवल हम सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं अपितु असत्य को पूरी शक्ति के साथ सत्य सिद्ध करने के प्रयास कर रहे हैं। इसका नवीनतम उदाहरण कुल्लु दशहरा तथा श्री रघुनाथ मंदिर से जुड़ी परंपरा का है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किसी भी धार्मिक स्थान तथा उत्सव में बलि चढ़ाने की परंपरा को बंद करने के आदेश पारित किए। पहाड़ों में यह परंपरा बनी है कि देवताओ को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बेजुबान मेमनों, भेड़–बकरियों की मंदिरों में बलि चढ़ती है। इस बेतुकी राक्षस परंपरा से तो यही समझ आता है कि हम राक्षसों, भूतों को प्रसन्न कर रहे हैं यदि इनका अस्तित्व है तो..... न कि ईश्वरीय शक्ति को जो कभी किसी का अहित नहीं चाहती है। मनुष्य ने कभी स्वयं की बलि देने की तो नहीं सोची पर दूसरों असहायों की अवश्य ही। दूसरों असहायों की जगह यदि कभी शेरों की बलि देने की सोची भी होती तो आटा–चावल के भाव समझ में आता! उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों ने कुल्लु दशहरे के संदर्भ में परंपराओं को ढाल बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलीलें देकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बना दिया। जिन रघुनाथ (श्रीराम) ने जीवन भर नैतिकता, सदाचार व आदर्श स्थापित करने के लिए पीड़ा सहन की, उन्हीं की आड़ में आज बेजुबान मेमनों की बलि चढ़ाने की बात से याचिककर्ताओं को क्या लाभ मिलेगा, यह समझ से परे हैं। इसकी क्या हानि हो सकती है यह अवश्य एवं सहजता से समझ आता है। कहते हैं.....प्रसन्नता बांटने से कई गुणा अधिक प्रसन्नता मिलती है तथा कष्ट बांटने से कई गुणा अधिक कष्ट की प्राप्ति होती है। मेमनों के कटने से होने वाले कष्ट अपना प्रभाव कैसे छोड़ेंगें....यह भविष्य के गर्भ में हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष एक हज़ार से अधिक लोगों की जान भू–स्खलन तथा सड़क दुर्घटनाओं से होती है। यदि यह वास्तव में देवभूमि होती तो देवतागण इन आकस्मिक मृत्यु से रक्षा अवश्यक करते। क्योंकि हम अपने कर्मों से इसे दैत्य भूमि बनाने में लगे हैं तो इसका कोप होना अनिवार्य है। कर्मों की गति पर टीका करने वाले लोग इसे इन कुरीतियों के दुष्परिणाम के रुप में भी देखने लगे हैं। वनों को काट कर अपनी भूसंपत्ति का विस्तार कर हमने हिमालय में बैठी सभी दैविक शक्तियों को कुपित कर दिया है। अपने फलों, सब्जियों आदि के उत्पादन मे हम प्रचुर मात्रा में प्राणघातक कीटनाशकों के प्रयोग से हमने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे नारायण को कुपित करना आरंभ कर दिया है। आखिर यह कोपभाजन कहीं न कहीं तो होना ही है, तथा इसके जिम्मेवार कोई और नहीं अपितु हम स्वयं ही है। प्रकृति की इस चेतावनी को अभी भी न सुना तो यह भयावक रुप ले सकती है। मनुष्य में विवेक आए, स्वार्थपरता तथा व्यैक्तिक अहंकार से ऊपर उठकर सर्वकल्याणार्थ सेवा करें। ऐसी सामाजिक सोच एवं विचार को परिपक्वव करने की आवश्यकता है। नहीं भूलना होगा कि.....कण–कण में नारायण है।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

Organic Fertilizer – The First Step to Organic Farming

With increase in demand for green products and pollution free agricultural products, the term 'organic' has become an irresistible trend of modern agriculture. Rapid development of organic agriculture coupled with augmenting demand for organic food is expected to increase the demand for organic fertilizers.

Globally organic fertilizers market is growing due to increasing population as well as their increasing willingness to pay for organic foods. Farmers' preference towards organic farming due to favourable pricing of the products has helped to increase the area under cultivation as well as growing agriculture land area for organic cultivation, has led to the increasing demand for organic fertilizers. The market players are responding to these new opportunities by expanding their service offerings/product lines, which has fuelled up the share of organic fertilizers in the global market. High nutritional benefits obtained from organic fertilizers are also supporting the sale of organic fertilizers globally.

The global organic fertilizers market is regionally segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World (RoW). Europe accounts for major market share followed by Asia Pacific for the organic fertilizers market. In Asia Pacific, due to strong government policies are contributory factor for the growth of organic fertilizers as well as availability of large agricultural land area.

If we talk from India's point of view, the country has substantial potential for expansion of organic agriculture owing to many factors, including favourable agro-climatic conditions. The rise in per capita purchasing power, accompanied by the increase in awareness regarding the social, environmental and health benefits of organic products, has not only increased the demand for such products but also incentivized the development of the organic value chain, as is evidenced by developments in industries such as e-commerce, supply chain, storage and processing. Despite the enabling environment created by a culmination of the aforementioned factors, there exist several challenges for all the stakeholders involved at every stage of the value chain. According to a research, Indian soil nutrient & Organic carbon contents is depleting due extensive farming & imbalance use of fertilizer. In India, Soil Organic Carbon contents varies between 0.2% to 0.5%, whereas ideally it should have been 1%. According to ISRO-led study, it was observed that nearly 30% of India's soil has undergone degradation while 25% of the country's geographic area is undergoing desertification; most of which is agricultural land. The conventional (that is, chemical farming) methods used are stripping the soil of its strength causing long-term damage. And this should raise alarm bells!

As per Govt. of India figures of 2013-14, 11.8 million acres of land in India are under organic certification, though this is largely for forest. Around 1.8 million acres is cultivable land is under organic certification. Currently India ranks 33 in terms of total land under organic cultivation and 88 in terms of the ratio of agricultural land under organic crops to total farming area. To facilitate organic farming, 11 state governments (Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Nagaland, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Odisha) have come out with their own State Organic Farming Policies, and as we all know, Sikkim has become the first state to be declared as Organic State.

Agriculture which is the mainstay of people in Himachal Pradesh, provides direct employment to 69 per cent population. To ensure balanced use of nutrients, over four lakh soil cards have been issued to the farmers. If government's data are to be believed, farmers in Himachal Pradesh's landlocked valleys like Pangi in Chamba district and Dodra Kwar in Shimla district have never used pesticides and fertilisers for growing crops. The government data also shows that chemicals are in least use in Himachal Pradesh in comparison to other states of the country. As per an agriculture survey, there is a scanty use of chemicals in the State i.e. 158 grams as against 381 gms per hectare average in the country. The Hon'ble Governor of Himachal Pradesh, Shri. Acharya Dev Vrat's Zero Budget Natural Farming project with the motive that farmers of the state would adopt organic farming is a step forward for the State.

Under Mission RIEV, the process propagating the concept of going organic has seen creation of partnership between the farmers and public in general. Today Mission RIEV is sitting on 15 lakh Kgs of organic manure developed out of house-hold bio-waste under unique business model, wherein the technological knowhow is shared with prospective manufacturers across Panchayat's by our Agriculture Specialists and supported by Panchayat Facilitators. With a buy back scheme, Mission RIEV is ensuring sustainability and bringing about a behavioural change and shift from Chemical to Organic fertiliser. Not only this, Mission RIEV has developed unique method of customising organic manure as per individual land's soil nutrient need. For Mission RIEV it's a small step towards the ultimate goal in converting Himachal Pradesh into an Organic State.

Anand Nair, Managing Editor
anand@iirdshimla.org

दरक रहे हैं पहाड़...भविष्य सुरक्षित नहीं

विकास और स्वार्थ के नाम पर प्रकृति के शोषण से गंभीर परिणाम होंगे भुगतने

देश में प्रकृति के बदलते मिजाज़ ने भविष्य की चुनौतियों को सामने खड़ा कर दिया है । हम भूगोल को पुस्तकों से बाहर अपनी दिनचर्या में चर्चा का विषय तो शायद अक्सर ही बनाया करते हैं किंतु भूगोल का मानचित्र अब विनाश के कगार पर पहुंचता जा रहा है । धरती बड़ी तीव्रता से बदलती जा रही है । यह अनुमान नहीं बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा भी इसकी पुष्टि समय–समय पर की जाती रही है । धरती के भीतर भी भूखंड एक–दूसरे से अलग हो रहे हैं । यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है लेकिन इतनी तीव्रता से जलवायु परिवर्तन खतरे की घंटी है ।

वर्ष 2018 भारी परेशानी लेकर आया और आखिरी महीनों में भी जम कर उत्पात मचा रहा है । सितंबर माह में भी वर्षा और तुफान ने हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है । वर्तमान तक 1250 करोड़ से अधिक का नुकसान प्रदेश सहन कर चुका है और अभी मौसम के तेवर अनुमान में भी कड़े के कड़े ही नज़र आ रहे हैं । यही हाल पूरे देश में लगभग अधिकतर राज्यों का है । विशेष रुप से पहाड़ी राज्यों में तो आपदाओं ने सब कुछ तहस–नहस कर दिया है । उत्तराखंड का आंकड़ा चौकाने वाला है । हर ओर भूस्खलन और बारिश से तबाही । हिमाचल को भी इससे अछूता नहीं रखा जा सकता है । बादल फटने और अनियंत्रित वर्षा ने ज़मीन को तो अपने स्थान से खिसका ही दिया है परंतु पहाड़ों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है । चंबा और कुल्लु ज़िलों में तो स्थानीय लोगों को बेघर होने जैसी स्थिति बन गई । इतना ही नहीं हज़ारों लोग, बच्चे, सरकारी अधिकारी फंस गए । उन्हें जैसे–तैसे बचाव कर्मियों ने वहां से निकाला । हिमाचल प्रदेश अपनी दुर्गति के लिए कहीं न कहीं स्वयं ही जिम्मेवार है ।

सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गो एवं फोर लेन परियोजनाओं ने हिला दिए पहाड़

बेहद खूबसूरती और स्वच्छ जलवायु के लिए जाना जाने वाला हिमाचल आज बेइंतहाशा खनन के कारण दरक चुका है । सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया आज घर आंगन तक ले जाने के लिए निरंतर जारी है । प्रत्येक व्यक्ति अपने आंगन तक ही सड़क पहुंचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार है । इसके लिए पहाड़ों में जहां–तहां से जेसीबी मशीने दनदनाती हुई पहाड़ों को सीना चीर रही है । इसमें कोई शंका ही नहीं है कि आज सड़के इंसान की जीवन रेखा है किंतु इसके लिए लिंक से लिंक जोड़कर सड़कों का मायाजाल बिछाया जा चुका है । कुर्बानी तो पेड़–पौधों और मूक पहाड़ को ही चुकानी पड़ रही है । उस पर अंधाधुंध राष्ट्रीय राजमार्गों एवं फोरलेन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है । फोर लेन के बनने का कार्य जब से आरंभ हुआ है तब से भूस्खलन, ज़मीन धंसने आदि की घटनाऐं भी बढ़ गई है ।

हिमाचल के संदर्भ में परमाणु से शिमला तक ही बात करें तो सैंकड़ों जेसीबी मशीनों के पंजों ने पहाड़ों को खंरोच कर इसकी नींव ही हिला दी है । परमाणु, सोलन और शिमला तक हज़ारों पेड़ों को शहीद करने के बाद चट्टानों की पेट पर ठोकर मार कर पहाड़ों का गर्भपात करवाया जा रहा है । इस पर विडंबना यह कि पेड़ों के लगाने के प्रति निराशा और लापरवाही बरती जा रही है । ऐसा विकास जो वर्तमान में नुकसान और भविष्य को विनाश के कगार पर खड़ा कर दे....उसको जिन शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए वो शायद मिल न पाए । पहाड़ों पर मकान बने हैं और उसके बिल्कुल नीचे खनन और सड़क के लिए मशीनें लगी है । ऐसे में कंकरीट के जंगल यानि मकानों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है । सरकार और एजेंसियों के मध्य होने वाले अनुबंध को क्या पूरी तरह से लागु ही नहीं किया जाता है ? मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में एक जैसे फार्मुले पर सरकार जब कार्य करती है तो इसकी सफलता पर संदेह होना निश्चित है ।

क्या कहते हैं बुजुर्ग परसराम

वयोवृद्ध परसराम पुराने दिनों के हिमाचल को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत सुंदर और हराभरा प्रदेश उन्हें अब अच्छा नहीं लगता है । उन्होंने पुरानी यादों में खो जाने के बाद कहा कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉ0 यशवंत सिंह परमार कहते थे कि गांव को एक ही सड़क मुख्य सड़क से लिंक होनी चाहिए ताकि उस संपर्क सड़क के माध्यम से किसानों की सब्जियां आदि बाज़ारों तक लाई जा सके । परंतु आज तो जितने लोग उतनी सड़कें.....क्या हासिल होगा पहाड़ों को तोड़ने और काटने से ?

पहाड़ों को बचा लो गर बचा सकते हो

आईआईआरडी के चेयरमैन एवं समाजसेवी पर्यावरणविद प्रोफेसर आर के गुप्ता के अनुसार उन्होंने जीवन भर जल–जंगल–ज़मीन के संरक्षण पर सेवाऐं दी और आज भी नई पीढ़ी को पहाड़ों को बचाने की शिक्षा ही देता हूं । उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रदेश को बर्बाद कर देंगे और इतना अधिक खनन पहाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । पानी को रोकना भी खतरनाक और न रोकना भी नुकसान में होता है । इसके लिए योजनाबद्ध तरीक़े से कार्य करने की आवश्यकता है ।

पहाड़ों की पोषक एवं उपजाऊ मिट्टी मैदानों को करती है गुलजार

हिमाचल में वर्षा जल संग्रहण की ठोस नीति अभी भी कारगर रुप से कार्य नहीं कर पा रही है । भूस्खलन में भारी वर्षा भी एक अहम कारण है क्योंकि हमारे पास अभी भी जल प्रबन्धन की तकनीक का अभाव है । जलागम परियोजना ने हालांकि प्रदेश में एक सुनियोजित तरीके से जल प्रबंधन और भूमि कटाव को रोकने के लिए बेहतर कार्य किया है किंतु इसे भी वांछित सफलता प्राप्त हो चुकी है, इसमें संदेह है । नालों से पानी धीरे–धीरे मिट्टी को स्खलित करते हुए ज़मीन धंसती रहती है । इसके लिए प्रत्येक नालों में छोटे से बड़े चैकडैम बनवाकर मिट्टी को रोका जा सकता है । अन्यथा ज़मीन की उपरी सतह की उपजाउ मिट्टी बह कर मैदानों को निकल जाती है और शेष बच जाता है पत्थरों की रेतीली ज़मीन । जब से पहाड़ नंगे हुए हैं मौसम ने भी अपना मिजाज़ बदल दिया है । बेमौसमी और अनियंत्रित वर्षा से जनजीवन के साथ–साथ पर्यावरण का भी भारी नुकसान हो रहा है । मात्र नालों आदि से ही नहीं वरन् खेतों की पोषक तत्वों का भी क्षरण होता जा रहा है ।

अनियोजित जल ठहराव करना विपदा को न्योता

2018 भारत के लिए जल प्रलय बन कर आया है । पूरा भारत जलप्रलय की विनाशलीला देख चुका है । केरल में तो अब तक की सबसे बड़ी आपदा सामने है । हज़ारों बेघर हो चुके हैं और कितनों को इस विनाश लीला का ग्रास बनना पड़ा है । ऐसा क्यों हुआ ? केरल में जब बांध का पानी छोड़ा गया तो इससे पानी ने अपने बहाव में केरल का अधिकतर क्षेत्र ले लिया । उस पर बारिश का कहर......सब तहस–नहस हो गया । केरल को कितने ही वर्ष पीछे कर दिया इस आपदा ने । इसके लिए जल ठहराव का सुनियोजित प्रबंधन होना आवश्यक है । ये बांध हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत तो हो सकते हैं किंतु यही बांध बाद में प्रलय का कारण भी बन जाते हैं । जल संचय और निकासी की कारगर नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है ।

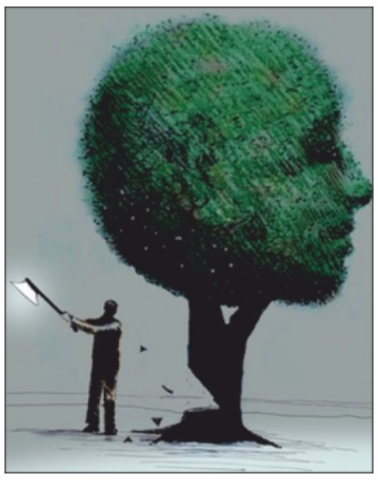

वृक्ष कटान : गला घोंटने जैसा कृत्य

विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही वृक्षों के संरक्षण की बात करते हैं । इसके पीछे बहुत से कारण हैं । ब्रह्मांड में तो असंख्य ग्रह है जो बिना वृक्षों या पौधों के हैं इसलिए वहां जीवन भी संभव नहीं है । पृथ्वी पर वृक्ष हैं तो यहां जीवन भी है । ये वृक्ष ही हमें ऑक्सीजन प्रदान कर हमारी सांसों को जीवन दिए हुए हैं । यही वृक्ष हमारे पर्यावरण संतुलन का आधार भी है । ऐसे में क्या ईश्वरतुल्य इन वृक्षों को इस प्रकार काट–काट कर धरती को नग्न करने की कुत्सित प्रक्रिया कब तक चलेगी ? और यदि सहज विकास के लिए यह किसी हद तक आवश्यक भी है तो फिर उसके विकल्प के रुप में हमने कौन सा मार्ग खोजा है या एक वृक्ष के स्थान पर कितने वृक्षों को रोपित करने का संकल्प लिया है ? इसे कब दस्तावेज़ी कब्रगाह से निकाल कर व्यवहारिकता का चोला पहनाया जाऐगा.....किसे मालूम ? 33 करोड़ देवताओं को समेटे किसी भी वृक्ष की वंदना करने का अभिप्राय उसकी प्राणदायी गुणवत्ता के कारण है न कि अन्यत्र किसी भी दर्शन को सार्थक कर उसकी बलि देने में है । ऐसे में वर्षों की धूप,बारिश और तूफानों को झेलता हुआ प्राणदायी वृक्ष हमारी स्वार्थ की हवस का शिकार होकर कुछ ही मिनटों में जंमीजोद हो रहा है । यह प्रकृति के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? विनाश की लीला का रंगमंच तो हम स्वयं ही तैयार कर रहे हैं । विशेष तौर पर पहाड़ इस विपदा को सहन नहीं कर पा रहा है और मनुष्य और प्रकृति में होने और न होने के मध्य के इस रण में मानुष विनाश ही होगा...इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए ।

भीषण आपदा के संकेत

अवैध और अंधाधुंध खनन, विकास की धूरी कही जा रहीं सड़कों के जंजाल, वृक्षों के कटान, गांव एवं शहरों को कंकरीट के जंगल में तबदील करना, अनियोजित जल प्रबन्धन एवं भविष्य के लिए कोई कारगर नीति का न होना किसी भी भीषण आपदा के प्रबल संकेत हैं । इसका आरंभ तो हो ही चुका है । ऐसे में अब पहाड़ों को बचाने और ज़मीन–मिट्टी के संरक्षण के लिए एक सौ पच्चीस करोड़ लोगों का सामुहिक उत्तरदायित्व बन जाता है । पहले मंदिर पहाड़ों की चोटी पर हुआ करते थे और लोग अपने मकान को धरातल में खेतों और नदी नालों के साथ बनाते थे । इसलिए पहाड़ों की उंचाई नंगे पैरों से मापी जाती थी और एक आस्था का केन्द्र होते थे पहाड़ । लेकिन वर्तमान कितनी तेजी से बदला है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज आदमी ने स्वयं की आरामगाह और शमशान को पहाड़ ही चोटी पर पहुंचाया है और मंदिर को अब सड़क के बड़े मोड़ के किनारे या धरातल पर स्थापित कर अपनी आधुनिकता का परिचय दिया है । स्वयं पहाड़ों पर रहना और उसके नीचे से बड़ी–बड़ी सुरंगों का निर्माण कर पहाड़ को अंदर ही अंदर से खोखला किया जा रहा है । ऐसे में आपदा विपदा बनकर किस समय टूटेगी......कहना मुश्किल है ।

समाधान क्या ?

यह जानते हुए भी कि समस्या गंभीर है, हम आंखे मूंद कैसे बैठ सकते हैं ? इसलिए इसके समाधान का उत्तरदायित्व हम सब पर है । यदि कारणवश वृक्ष काटा भी जा रहा है तो उसके विकल्प के रुप में कितने वृक्ष न केवल लगाने है बल्कि उसके संरक्षण को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना होगा । सड़कों का निर्माण इस प्रकार और इतना ही हो जिससे कि प्रकृति के सीने पर खनन की खरोंच कम हो या न के बराबर हो । विकास का आधार कहीं न कहीं मनुष्य के होने के साथ ही हैं, उसके विनाश की भूमिका को बांधने वाला विकास सर्वथा त्याज्य है । भयंकर वर्षा और अनियंत्रित जल प्रलय के समुचित प्रबन्धन की प्रबल आवश्यकता है । जलागम प्ररियोजना एवं जल प्रबन्धन विकास को सही तरीके से लागु करने और इसके दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर खाका तैयार करने की भी ज़रुरत है । आओ पहाड़ों से दोस्ती करें......प्रकृति से प्रेम........इसकी सुंदरता और विलक्षणता को सहेजने मे सहयोग करें ....कहीं ऐसा न हो कि दरकते पहाड़ों को ज़ख्म देने की इस अंधी दौड़ में हम अपने अस्तित्व हो ही न मिटा दें ...आओ पहाड़ों से दोस्ती करें...प्रकृति से प्रेम...

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

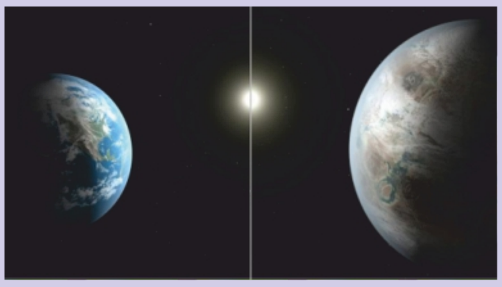

हमारी प्यारी पृथ्वी का अंत

पृथ्वी, जिसे हम अपनी धरती कहते हैं उसकी उम्र भी सीमित है । अब धरती के पास सिर्फ 3 से 5 अरब साल बचे हैं । तब तक इंसान बचेगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है ।

परिक्रमा करने में छटपटाहट

सूर्य और चंद्रमा लगातार अपनी गुरुत्वीय ताकतों से पृथ्वी की परिक्रमा को रोकने की कोशिश करते हैं । वैसे जिस दिन यह परिक्रमा रुकेगी, उसी दिन जीवन तो करीब करीब खत्म हो जाएगा ।

सूर्य से शुरुआत, सूर्य से अंत

सूर्य, ब्रह्मांड में मौजूद इस महातारे की मदद से धरती पर जीवन फलता है । लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही सूर्य धरती का पूरा विनाश भी करेगा ।

कहां छुपे इंसान

वैज्ञानिक रूप से इन दावों की पुष्टि के चलते ही इंसान मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बनाने की सोच रहा है । वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में तकनीक इतनी आगे पहुंच जाएगी कि इंसान आराम से कहीं और बस सकेगा ।

प्रदेश के दो स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार

32 को राज्य स्तरीय सम्मान

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत प्रदेश के दो स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है। देशभर से चुने गए 52 स्कूलों में से बिलासपुर जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंद तीसरे नंबर पर, जबकि सिरमौर जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला धमून आठवें नंबर पर रही हैं। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 32 स्कूलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 32 स्कूलों का चयन हुआ। अक्तूबर महीने में सरकार इन स्कूलों के प्रभारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी।

अमेरिका में अपने सुरों का जादू बिखेरेगी मुस्कान

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए संगीत की दृष्टि बाधित छात्रा मुस्कान अपने सुरों का जादू अमेरिका में बिखेरेगी। अमेरिका में मुस्कान दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकी की भी जानकारी हासिल करेंगी। गायन के क्षेत्र में मुस्कान की उपलब्धियों को देखकर बंगलूरू की एक संस्था ने उन्हें अमरीका में हो रहे कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए चुना है।

मुस्कान के साथ दक्षिण भारत की तीन दृष्टि बाधित एवं दो बधिर छात्राएं भी अमेरिका गई हैं, जो नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मुस्कान को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल का यूथ आइकॉन घोषित किया था। मुस्कान ने हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।

हिमाचल की बेटी को नेशनल एडवेंचर अवार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मोहल की रहने वाली बेटी प्रतिभा को अब साहसिक खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। भारतीय नौ सेना में सेवाएं दे रही लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड–2017 से नवाजा गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते 25 सितंबर को नई दिल्ली में प्रतिभा को इस अवार्ड से सम्मानित किया। प्रतिभा को अब तक नारी शक्ति अवार्ड और 15 अगस्त को नौ सेना मेडल से नवाजा जा चुका है।

रिकार्ड 254 दिनों तक समुद्र की प्रचंड लहरों का सामना कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली जांबाज अधिकारियों की टीम तारिणी की यह यात्रा पिछले साल दस सितंबर को आरंभ हुई थी और यह विश्व की पहली ऐसी सागर परिक्रमा थी जिसमें सिर्फ महिला अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। यह यात्रा 21 मई 2018 को पूरी हुई थी। इस टीम में लैफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, प्रतिभा जंबाल, पी स्वाथी, लेफ्टिनेंट एशवर्य बी, पायल गुप्ता व विजया देवी शामिल थी।

वायुसेना के पायलट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारतीय वायुसेना के पायलट कार्तिक ठाकुर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लाहला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लडभड़ोल के कार्तिक की मौत कोलकाता में हुई थी। वायु सेना के अधिकारियों के अनुसार कार्तिक की मौत स्वीमिंग पुल में डूबने से हुई है।

59 की उम्र में प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने जोशी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जिला सोलन के धर्मपुर से संबंध रखने वाले बीके जोशी हिमाचल से पहले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। बीके जोशी (59) का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए मार्च 2018 में चंडीगढ़ में एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स से मलयेशिया में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। मलयेशिया के पिनांग में खेली गई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर हिमाचल के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। उनका 2021 में जापान में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है।

इंटर कॉलेज शूटिंग प्रतियोगिता में आरकेएमवी और संजौली विजेता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एचपीयू ने तीन साल से शूटिंग को अपने खेल कैलेंडर में शामिल किया है। पुरुष वर्ग में बीते वर्ष की विजेता जवाहर लाल नेहरू फाइन आर्ट कॉलेज की टीम ने दूसरा और सेंटर फार इवनिंग स्टडीज इवनिंग कॉलेज ने तीसरा स्थान पाया। महिला वर्ग में सीमा कॉलेज रोहड़ू ने दूसरा और नालागढ़ कॉलेज ने तीसरा स्थान पाया। प्रतियोगिता में एचपीयू से संबद्ध 20 कॉलेजों के 139 शूटरों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में प्रदेश राइफल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरत सिंह, विरेंद्र बांशटू, वीर सिंह, टीकाराम ने तकनीकी सहयोग किया।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल 16वें स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हिमाचल नए उद्योगों को माहौल दे पाने में देशभर में 17वें से 16वें पायदान पर पहुंच पाया है। उद्योगपतियों की पहली पसंद तेलंगाना है जबकि हरियाणा टॉप थ्री और उत्तर प्रदेश टॉप टेन में शामिल हैं।

हिमाचल में नए उद्योग न आ पाने का सबसे बड़ा कारण कच्चा माल महंगे दामों पर उपलब्ध होना माना जा रहा है। हिमाचल शांत प्रदेश है, यहां विभिन्न विभागों और सरकार का सहयोगात्मक रवैया रहता है। बावजूद इसके उद्योग स्थापित कराने के माहौल में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है।

उत्तर भारत का सबसे बड़ा मशरूम प्लांट धर्मपुर में

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

उत्तर भारत का सबसे बड़ा मशरूम प्लांट धर्मपुर में 103 बीघा जमीन पर बनेगा। 423 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस प्लांट के लिए क्षेत्र के सिद्धपुर में साइट चिह्नित की गई है। यह जमीन फिशरीज विभाग के नाम पर प्रस्तावित थी लेकिन फिश फार्म प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर के मछयाल में शिफ्ट हो गया है, जिससे यह जमीन खाली पड़ी है।

तकनीकि विवि से भी कर सकेंगे पत्रकारिता की पढ़ाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अब युवा कम्युनिटी रेडियो और जर्नलिज्म की पढ़ाई हमीरपुर स्थित टेक्निकल विवि में भी कर सकेंगे। विद्यार्थियों को विवि के अपने कैंपस में पत्रकारिता में पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर अगले सत्र से ये विषय शुरू करने जा रहा है।

सुधीर शर्मा बने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता को पार्टी ने जम्मू–कश्मीर का प्रभार भी सौंपा है। गौरतलब है कि सुधीर शर्मा के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 8 अन्य नेताओं को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया।

मौहल में कूड़ा संयत्र का विरोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मौहल के पिरड़ी स्थित कूड़ा डंपिंग साइट को लेकर विरोध जारी है। इस साइट को लेकर 15 सितंबर से बल्ह पंचायत के साथ वन अधिकार समिति कूड़ा फेंकने का विरोध कर रही है और संयंत्र को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद भी किया गया। विरोध में लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

नई राहें नई मंजिलें से विकसित होंगे ये पर्यटन स्थल

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत तीन स्थानों का चयन किया है। मंडी जिले के जंजैहली, शिमला के चांशल और कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को इस योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

मारकंडा मंदिर और अंबिका माता मंदिर में सामुदायिक हॉल के अलावा जंजैहली, शटाधार, कुथाह, शिकारी माता मंदिर आदि में लगभग 2.70 करोड़ रुपये की लागत से सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

क्षेत्र के विकास व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुल 16.70 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से 25.17 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटक संस्कृति केंद्र को विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बीड़ बिलिंग में 8.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पैराग्लाडिंग संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के तीन बांधों में शुरू होंगी जल परिवहन सेवाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार हिमाचल में जल परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में यह सेवा बिलासपुर में भाखड़ा, चंबा में चमेरा और मंडी स्थित कोल बांध में सेवा शुरू की जाएगी। जल परिवहन की संभावनाओं पर आईटी मैरीटाइन प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इन तीनों बांधों पर जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने को 26.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बीते दिनों जल परिवहन पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परामर्श एजेंसी की ओर से सौंपी रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा बांध पर 91 किलोमीटरए कोल बांध में 52 और चमेरा में 27 किलोमीटर में जल परिवहन सुविधा मिलेगी। रिपोर्ट में भाखड़ा बांध पर 21.86 करोड़ए चमेरा पर 2. 69 करोड़ और कोल बांध पर 1.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

प्रदेश हाईकोर्ट की अधिवक्ता सुनीता शर्मा राज्य उपभोक्ता आयोग की नई सदस्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

प्रदेश हाईकोर्ट की अधिवक्ता सुनीता शर्मा राज्य उपभोक्ता आयोग की नए सदस्य होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश, एम खानविलकर व न्यायाधीश वाइवी चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रदेश उच्च न्यायालय के पारित फैसले पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा को एक माह के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग का सदस्य नियुक्त करने के आदेश पारित किए थे। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था। साथ ही हाईकोर्ट ने मीना वर्मा की नियुक्ति को कानून के विपरीत पाते हुए रद कर दिया था।

4 दर्रों से गुजरने वाले विश्व के सबसे ऊंचे रूट पर बस सेवा बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दिल्ली से लेह के बीच चलने वाली बस सेवा को अगले साल के लिए बंद कर दिया है। 1043 किलोमीटर लंबे इस रूट पर खराब मौसम और बर्फबारी के चलते बस सेवा बंद कर दी गई है। अब यह सेवा केलांग तक ही संचालित होगी। वर्तमान में यह बस देश के उन सबसे दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है, जहां साल भर बसों का संचालन करना बेहद मुश्किल है। दिल्ली से लेह तक के रोमांचक सफर में यह बस रोहतांग पास (13050 फीट), बारालाचा पास (16043 फीट) और तंगलांगला (17480 फीट) और लाचुंगला पास (16598 फीट) से गुजरती है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

हिमाचल सार

प्रिय पाठकों, द रीव टाइम्स को आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस समाचार पत्र को और अधिक ज्ञानवर्धक बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगात्मक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी पाठकों के लिए प्रस्तुत है बिते 15 दिनों की घटनाओं पर आधारित प्रश्नावली :

1	प्रदेश के किन दो स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार मिला	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंद जिला बिलासपुर व राजकीय माध्यमिक पाठशाला धमून, सिरमौर
2	उत्तर भारत का सबसे बड़ा मशरूम प्लांट कहां पर स्थापित किया जाना है	धर्मपुर
3	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन किसे चुना गया है	सुधीर शर्मा
4	विगत विधानसभा चुनाव में किस दृष्टिबाधित छात्रा को यूथ आइकॉन घोषित किया गया था	मुस्कान
5	नई राहें नई मंजिल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है	पर्यटन
6	हिमाचल के किन तीन स्थानों को नई राहें नई मंजिल योजना के तहत विकसित किया जाएगा	मंडी के जंजैहली, शिमला के चांशल और कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को
7	हिमाचल की किस बेटी को तेनजिन नॉर्गे अवार्ड के लिए चुना गया है	प्रतिभा जंबवाल, जिला कुल्लू, गांव मोहल
8	इंटर कॉलेज प्रतियोगिता ने किन कॉलेजों ने बाजी मारी	आरकेएमवी और संजौली
	विश्व का सबसे ऊंचा बस रूट कहां पर है	दिल्ली से लेह रूट
9	हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है	सुनीता शर्मा
10	हिमाचल में कहां पर जल परिवहन योजना शुरू की जानी है	भाखड़, कोल आरे चमेरा
11	इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल का कौन सा स्थान है	16वें स्थान पर
12	हाल ही में किस राज्य में बस किराया बढ़ाया गया है	हिमाचल
13	कहां पर कूड़ा संयत्र को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया	कुल्लू के मैहला में

मंत्रिमंडल फैसले

आईसीएआई तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

इससे संयुक्त शोध, गुणवत्ता समर्थन, क्षमता सृजन, प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान–प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी और निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों के आयोजन में सहायता मिलेगी। आईसीएआई तथा आईसीपीएके दोनों संस्थानों के कर्मियों को कार्यक्रम के अनुसार सहमति वाले औपचारिक कार्य प्लेसमेंट के जरिए अवसर प्रदान करेंगे। जागरूकता बढ़ाने तथा आईसीएआई/आईसीपीएके की रणनीतिक साझेदारी की गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा और समझौता ज्ञापन में दिए गए क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास की रणनीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा लागू करने में सहयोग की संभावना तलाशना है। इसमें एक दूसरे की शक्तियों, बाजार, प्रौद्योगिकी, नीतियों आदि को समझने के लिए ढांचा और अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (एनडीसीपी–2018) तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम 'डिजिटल संचार आयोग' देने की स्वीकृति दे दी है।

एनडीसीपी–2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना से नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।

पटना हवाई अड्डे पर नया घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना निर्माण की स्वीकृत

मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने पटना हवाई अड्डे पर 1,216.90 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से नया घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना के निर्माण को अपनी स्वीकृति दे दी है।

नया टर्मिनल भवन बनने के बाद हवाई अड्डे की यात्री क्षमता बढ़कर प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन हो जाएगी. अभी हवाई अड्डे की यात्री क्षमता प्रतिवर्ष 0.7 मिलियन है।

नया टर्मिनल भवन 65,155 वर्ग मीटर का होगा जिसमें 18,650 वर्गमीटर क्षेत्र भूतल होगा. इस भवन को विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

नया टर्मिनल भवन बनने से पटना क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। इस परियोजना के साथ बिहार के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं।

यह परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित पैकेज का अंग है। बिहार का पटना हवाई अड्डा पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख हवाई अड्डों में एक है। हवाई अड्डे का वर्तमान टर्मिनल भवन दो मंजिला पुराना ढांचा है और इसका उपयोग क्षमता से चार गुणा अधिक किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की सरकारों को हस्तांतरित (विनिवेश) करने की स्वीकृति

मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने विनिवेश नीति का अनुसरण करते हुए आईटीसी की संपत्तियों/इकाइयों/ संयुक्त उद्यमों का आगे विनिवेश की मंजूरी दे दी है। यह विनिवेश होटल गुलमर्ग अशोक, गुलमर्ग तथा होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना की अधूरी परियोजनाओं को क्रमशः जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की सरकारों को हस्तांतरित (विनिवेश) करके किया जाएगा।

भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी)केहोटलों/संपत्तियों/इकाईयों /संयुक्त उद्यमों को पट्टे/उपपट्टे पर राज्य सरकारों को देना का निर्णय लिया गया था।

पट्टे/उपपट्टे के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की सहमति न होने की स्थिति में संपत्तियों को अधिकारिक अंकित मूल्य पर राज्य सरकारों को वापस देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया था. यह नीति इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि पेशेवर तरीके से होटलों को चलाना और उनका प्रबंधन करना सरकार या उसकी कंपनियों का काम नहीं है।

देश में आवश्यकता से अधिक चीनी उत्पादन से निपटने के लिए विस्तृत नीति को मंजूरी

मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने आगामी चीनी सीजन 2018–19 में अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए लागत संतुलन बनाकर चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 5500 करोड़ रूपये की कुल सहायता की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से देश से चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और चीनी उद्योग को किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

चीनी सत्र 2018–19 में निर्यात बढ़ाने के लिए आंतरिक परिवहन, ढुलाई, हैंडलिंग तथा अन्य शुल्कों पर आय का खर्च वहन करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी।

किसानों की बकाया गन्ना राशि चुकाने में चीनी मिलों की सहायता के लिए सरकार ने चीनी मिलों को चीनी सत्र 2018–19 में 13.88 रूपये प्रति क्विंटल पेरे हुए गन्ने की दर से वित्तीय सहायता दी का निर्णय लिया है, ताकि गन्ने की लागत का समायोजन हो सके।

किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रकार की सहायता राशि चीनी मिलों की ओर से सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

रेवाड़ी रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिहार शेल्टर होम मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवाड़ी रेप मामले की पीड़िता की पहचान उजागर होने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर कर नियमों की अवहेलना की गई है । इसका जिम्मेदार कौन है ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की की पढ़ाई से संबंधित बात बताई गई । इससे उसकी पहचान करना मुश्किल नहीं है । सबने ये कह कर खबर चलाई कि लड़की कौन है, सब जानते हैं इसको । कोर्ट ने कहा कि हमने पीड़ित के पिता का इंटरव्यू देखा है । जब पिता का चैनलों पर इंटरव्यू हुआ था तब उसके घर में 50 लोग थे, उन 50 लोगों ने बाकी लोगों को बताया होगा इस तरफ से पूरा देश इसके बारे में जान गया होगा । इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कोई गाइड लाइन है? AG ने कहा कि राज्य सरकार और चैनलों को नोटिस जारी कर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हालांकि कोर्ट में फिलहाल कोई आदेश नही दिया है।

देश के तकरीबन 40 फीसद स्कूलों में खेल का कोई मैदान ही नहीं, कहां खेलें बच्चे?

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देश में सिर्फ पंजाब एक राज्य ऐसा है जहां तकरीबन सभी स्कूलों में खेलने का मैदान है। यहां लगभग 98.57 फीसद स्कूलों में मैदान है। चंडीगढ़ में 92.54 फीसद स्कूलों के कैंपस में खेलने की सुविधाएं मौजूद हैं। कर्नाटक के पचास हजार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में से 50 फीसद में कोई मैदान नहीं है। शहरों की बात करें तो देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के 75 फीसद स्कूलों में कोई खेल का मैदान नहीं है। सीबीएसई के दिशा–निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूलों में 200 मीटर ट्रैक और खेलने की पर्याप्त सुविधाएं होना अनिवार्य है।

RRB Recruitment 2018 : रेलवे ने 2 हजार 600 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानिए क्या है योग्यता

उत्तरी रेलवे ने ट्रैक मैन के 2600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है । रेलवे ने ये वैकेंसी रिटायर या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए निकाली हैं । इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल है । आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं । आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है । 18 सितंबर को दूसरे दिन की भर्ती परीक्षा होगी। भर्ती परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड होगी । वैकेंसी से संबंधित जानकारी

पद का नाम..........ट्रैक मैन

पदों की संख्या...........2600

योग्यता–इन पदों पर सिर्फ रिटायर या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं ।

आयु सीमा–आवदेन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 65 साल निर्धारित की गई। **ऐसे करें आवेदन** –इच्छुक उम्मीदवार पीपीओ की मूल प्रति, सेवा प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्त पर जारी पहचान पत्र और IFSC कोड सहित मण्डल कर्मचारी अधिकारी, मुरादाबाद को भेज आवेदन सकते हैं ।

रुपये में गिरावट और बढ़ते चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने उठाए कदम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सरकार ने मसाला बांडों पर से विदहोल्डिंग टैक्स हटाने, विदेश संस्थागत निवेश के लिए ढील देने तथा गैर–जरूरी आयातों पर पाबंदी लगाने का शुक्रवार को निर्णय किया है । रुपये में गिरावट और बढ़ते चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है । अर्थव्यवस्था की सेहत की समीक्षा के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी । वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इन उपायों से 8–10 अरब डॉलर तक का सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है । बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश लगाने के लिए पांच कदमों पर निर्णय लिया है । उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा गैर–जरूरी आयात पर अंकुश लगाने का भी फैसला किया है ।

हालांकि, जेटली ने यह नहीं बताया कि किन जिंसों के आयात पर पाबंदी लगायी जाएगी. उन्होंने कहा, ''बढ़ते कैड के मामले के समाधान के लिये सरकार जरूरी कदम उठाएगी । इसके तहत गैर–जरूरी आयात में कटौती तथा निर्यात बढ़ाने के उपाय किये जाएंगे । जिन जिंसों के आयात पर अंकुश लगाया जाएगा, उसके बारे में निर्णय संबंधित मंत्रालयों से विचार–विमर्श के बाद किया जाएगा । वह डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के नियमों के अनुरूप होगा ।''

राष्ट्रीय समसामयिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 190 करोड़ रुपये के निवेश के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और पाइपलाइन परियोजनाओं का उद्घाटन किया?
बिहारः इ. उत्तर प्रदेश, ब. गुजरात,
क. महाराष्ट्र

2. हाल ही में किस राज्य ने पहली बार चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाने की घोषणा की?
हिमाचल प्रदेश : इ. केरल, ब. असम, क. अरुणाचल प्रदेश

3. केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कम्पनी के साथ मिलकर स्ववत्मअपमू अभियान लॉन्च किया? एप्पल : इ. गूगल, ब. रेडिफ, क. विप्रो

4. पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के तौर पर कंप्रेस्ड बायो गैस को बढ़ावा देने हेतु किस पहल का आरंभ किया?
स्टैट : इ. एडाप्ट, ब. क्लियरक, जेबीजी

5. विश्व में पहली बार किस देश में टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ?
दक्षिण अफ्रीका : इ. भारत, ब. ऑस्ट्रेलिया, क. कैरीबिया

6. किस देश ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसॉनिक विमान के तीन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
चीन : इ. नेपाल, ब.रूस, क. भारत

7. अमेरिका और किस देश के बीच 30 सितम्बर 2018 को नाफ्टा समझौते (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते) को लेकर सहमति बन गई?
नेपाल : इ.कनाडा, ब. चीन, क. भारत

8. तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल्स में भारतीय तीरंदाज़ दीपिका कुमारी ने महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में लिज़ा उनरू को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है?
रजत पदक, इ. स्वर्ण पदक, ब.कांस्य पदक क. इनमें से कोई नहीं

9. किस देश के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में छिपकली की दो नई प्रजातियां 'मॉन्टाने फॉरेस्ट' और 'स्पिनी–हेडेड फॉरेस्ट' खोजीं हैं? नेपालः इ.चीन, ब. रूस, क. भारत

10. हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ निम्न में से किसे चुना गया? शिखर धवनः इ.रोहित शर्मा ब. महेंद्र सिंह धोनी क. रविन्द्र जडेजा

उत्तरः

1.ब. गुजरात
विवरणः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के आनंद जिले के मोगार गांव में 190 करोड़ रुपये के निवेश के साथ किया।

2.ब. असम
विवरणः असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना की पेशकश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है.

3.इ. गूगल
विवरणः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान शुरू करने के लिए गूगल के साथ Loo Review हेतु साझेदारी की है।

4.. स्टैट
विवरणः स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतिम दिन 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक (स्टैट) पहल लॉन्च किया गया।

5.. दक्षिण अफ्रीका
विवरणः दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों के जन्म में सफलता हासिल की गई। ये शेर शावक कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए हैं।

6.. चीन
विवरणः चीन ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसॉनिक विमान के तीन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है।

7.इ. कनाडा
विवरणः अमेरिका और कनाडा के बीच 30 सितम्बर 2018 को नाफ्टा समझौते (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते) को लेकर सहमति बन गई। इस समझौते में मैक्सिको भी शामिल है।

8.ब. कांस्य पदक
विवरणः तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल्स में भारतीय तीरंदाज़ दीपिका कुमारी ने महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में लिज़ा उनरू को हराकर कांस्य पदक जीत लिया।

9 .क. भारत
विवरणः भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में छिपकली की दो नई प्रजातियां 'मॉन्टाने फॉरेस्ट' और 'स्पिनी–हेडेड फॉरेस्ट' खोजीं हैं. ये प्रजातियां पिछले 150 वर्षों से गलती से कॉमन गार्डन छिपकली की तरह पहचानी जाती रही हैं।

10.. शिखर धवन
विवरणः दुबई में 28 सितंबर, 2018 को यूनिमोनी एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर रिकॉर्ड सातवीं बार ख़िताब अपने नाम किया. मैन ऑफ़ द मैच रहे बंगलादेश की तरफ से शतक लगाने वाले लिटनदास (121), और मैन ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे शिखर धवन, जिन्होंने टूर्नामेंट में 5 इनिंग्स खेली और 342 रन

स्त्रोतः ऑनलाईन वेबसाईट

कैंसर के इलाज को आसान बनाने में मिली बड़ी सफलता

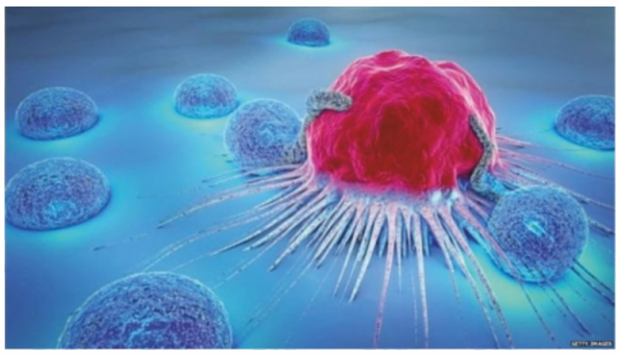

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पता लगाया है कि कैंसर कैसे बढ़ता है

इससे डॉक्टरों को मदद मिलेगी कि वो मरीजों के लिए सबसे प्रभावशाली इलाज कैसे शुरू करें ।

लंदन के इंस्टिट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च (आईसीआर) और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की टीम ने मिलकर एक नई तकनीक की खोज की है– रिवॉल्वर (रिपिटेड इवोल्यूशन ऑफ कैंसर) कैंसर के दौरान डीएनए में आए बदलावों के पैटर्न को ये तकनीक रिकॉर्ड करती है और इस जानकारी को भविष्य में होने वाले अनुवांशिक बदलावों को समझने के लिए इस्तेमाल करती है ।

शोधकर्ताओं का कहना है कि ट्यूमर में लगातार आते बदलाव कैंसर के इलाज में एक बड़ी चुनौती थी । एक कैंसर 'ड्रग रेसिस्टेंट' हो सकता है यानी कैंसर पर दवाई का असर बंद हो जाता है ।

हालांकि, अगर डॉक्टर ये पता लगा सकें कि ट्यूमर कैसे विकसित होगा तो वो इसके बढ़ने से पहले ही या इसके ड्रग रेसिस्टेंट होने से पहले ही इलाज शुरू कर सकते हैं ।

शोधकर्त्ता टीम को ट्यूमर में बार–बार आने वाले परिवर्तनों और कैंसर से बच जाने के बीच भी संबंध मिला है । इस तकनीक से डीएनए परिवर्तन के दोहराव का पैटर्न, कैंसर का पता लगाने में मदद कर सकता है और फिर इलाज भी उसी के मुताबिक होगा ।

उदाहरण के तौर पर, शोधकर्ताओं को पता चला कि जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर में ट्यूमर को रोकने वाले पी53 प्रोटीन की जीन में चूक होती है जिसके बाद क्रोमोजोम 8 में बदलाव होते हैं तो ऐसे मरीज कम बच पाते हैं ।

रिसर्च टीम ने एक नई मशीनी तकनीक बनाई है जो एक जैसे मरीजों के ट्यूमर की जानकारी बताती है। शोधकर्ताओं ने फेफड़ों, स्तन, गुर्दे और आंतों के कैंसर के लिए पिछले अध्ययनों के 178 रोगियों के 768 ट्यूमर सैंपल का इस्तेमाल किया और प्रत्येक ट्यूमर के डेटा का इस्तेमाल कैंसर का पता लगाने और हर कैंसर के परिवर्तनों की तुलना करने के लिए किया ।

गर्भवती महिला के सूप में मिला मरा हुआ चूहा फिर रेस्टॉरेंट ने दिया हैरान करने वाला ऑफर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन में एक गर्भवती महिला के सूप में मरा हुआ चूहा मिलने के बाद यहां के एक प्रसिद्ध रेस्तरां को बंद कर दिया गया । महिला ने आरोप लगाया है कि रेस्तरां के कर्मचारी ने उसे गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की स्थिति में गर्भपात कराने के लिए पैसे देने का ऑफर दिया । साऊथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला व उसका पति छह सितंबर को प्रसिद्ध जियाबु जियाबु रेस्तरां में खाना खा रहे थे, तभी उन्हें अपने हॉटपॉट में मरा हुआ चूहा मिला ।

महिला के पति ने कहा कि उन्होंने इस बारे में रेस्तरां के कर्मचारी को बताया और उसे गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ने पर गर्भपात कराने के लिए पैसे का ऑफर दिया गया । पति ने कहा कि उसे कर्मचारी ने कहा कि अगर आप शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो तो हम आपको गर्भपात कराने के लिए तीन हजार डॉलर (20 हजार युआन) दे सकते हैं ।

उसने अखबार को बताया, "रेस्तरां ने हालांकि कथित रूप से घटना के हर्जाने के तौर पर हमें बाद में 728 डॉलर (5000 युआन) दिए ।" स्वास्थ्य अधिकारियों ने रेस्तरां की जांच की, लेकिन चूहा होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि रेस्तरां को फिलहाल अन्य उल्लंघनों के लिए बंद कर दिया गया है ।

रोजाना एसप्रिन खाना हो सकता है खतरनाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रोजाना एक एसप्रिन लेना उम्रदराज लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है । अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है ।

दिल के दौरे के बाद अक्सर डॉक्टर एसप्रिन लेने की सलाह देते हैं क्योंकि ये दवाई खून को पतला करती है और दोबारा दिल के दौरे से बचाती है ।

यह बात साबित भी हो चुकी है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद एसप्रिन से फायदा होता है, लेकिन 70 साल की उम्र पार कर चुके स्वस्थ लोगों के मामले में ऐसा नहीं है ।

इस अध्ययन के मुताबिक 70 से ज़्यादा उम्र वाले स्वस्थ लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता है । यहां तक कि इस दवाई से उनमें आंतरिक रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों ने इन नतीजों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और खुद अपना इलाज करने को लेकर आगाह किया है क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ लोग भी एसप्रिन खाने लगते हैं ताकि दिल के दौरे का खतरा कम किया जा सके ।

19 हजार लोगों पर शोध

ये शोध अधेड़ उम्र के लोगों पर किया गया था। इसमें अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के 19,114 लोग शामिल थे जिन्हें उस वक्त तक दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं हुई थी।

इनमें से आधे लोगों को पांच साल तक रोजाना एसप्रिन खाने के लिए दी गई।

न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित तीन रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि उनमें न तो दिल की बीमारियों का खतरा कम हुआ और न ही कोई और फायदा हुआ। यहां तक कि इससे पेट में रक्तस्राव भी शुरू हो गया।

पाकिस्तान : इमरान सरकार को पैसों की दरकार कुल कर्ज बढ़कर हुआ 30,000 अरब रुपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पैसे की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की नयी सरकार किफायत बचाने के लिए लक्जरी कारों से लेकर भैंस तक की नीलामी कर रही है । नए प्रधानमंत्री इमरान खान की किफायत बरतने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास की 102 लग्जरी कारों में से 70 कारें सोमवार को नीलाम की गयीं । मीडिया की रपटों के मुताबिक, इन कारों के लिए बाजार से ऊंचा दाम मिला । अब प्रधानमंत्री आवास की आठ भैंसें बेचने की योजना है । खान के एक करीबी सहयोगी ने पिछले सप्ताह बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में आठ भैंसें पाल रखी थीं । इन्हें भी नीलाम किया जाएगा ।

पाकिस्तान सरकार पर कर्ज और देनदारियों का भारी बोझ है । प्रधानमंत्री के विशेष सहायक (राजनीतिक मामले) ने कहा कि सरकार मंत्रिमंडल के उपयोग के लिए रखे गए चार हेलीकॉप्टर भी नीलाम करेगी । इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है । पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि 70 कारों की पहली खेप बेची जा चुकी है । चौधरी ने दावा किया, "इन कारों को बाजार मूल्य अधिक दर पर बेचा गया है ।"

2025 तक मानव से ज्यादा काम करेंगे रोबोट, संभालेगा ये सारे काम

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 तक रोबोट मौजूदा कार्यभारों का 52 प्रतिशत कार्य संभालने लगेंगे, जो अब की तुलना में करीब दुगुना होगा ।

डब्ल्यूईएफ ने सोमवार को यह अध्ययन जारी किया. मंच का अनुमान है कि मानवों के लिये "नयी भूमिकाओं" में तेजी से इजाफा देखा जा सकता है ।

इतना ही नहीं मशीनों एवं कम्प्यूटर कार्यक्रमों के साथ हम कैसे कार्य करें और इनकी गति के साथ कैसे तालमेल बैठायें, इसके लिये मानव को अपने कौशल का उन्नयन करना होगा । स्विस संगठन ने एक बयान में कहा, "आज मशीनों के माध्यम से जहां 29 प्रतिशत कार्य हो रहे हैं वहीं वर्ष 2025 तक मौजूदा कार्यभारों का तकरीबन आधा मशीनों के माध्यम से सम्पन्न होगा ।"

70 साल बाद सुनाई दी बापू के दिल की धड़कन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

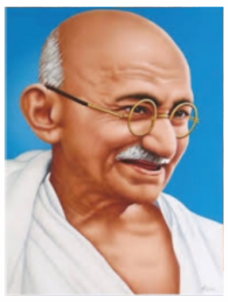

महात्मा गांधी की हत्या के 70 साल बाद राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में उनके दिल की धड़कन सुनाई दी। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब है लेकिन यह वैज्ञानिक सत्य है। राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के मौके पर संग्रहालय की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें गांधी के जीवन के दौरान किए गए ईसीजी की रिपोर्ट को जोड़ कर नये सिरे से उनके दिल की धड़कन का डिजिटल रूप तैयार किया गया।

संग्रहालय के निदेशक ए. अन्नामलाई के मुताबिक बापू के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर संग्रहालय अहिंसा व विश्व शांति के विषय पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर एक मल्टी मीडिया किट भी जारी की गई। इसमें बापू के जीवन से जुड़े ऑडियो व वीडियो फुटेज शामिल किए गए। इस किट को आम लोग 300 रुपये में खरीद सकेंगे। इस किट में गांधी लिखित 20 किताबों, उन पर लिखी गई 10 किताबों, गांधी के जीवन पर आधारित एके चेट्टियार द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री, उनके जीवन से जुड़ी 100 फोटोग्राफ, उनकी आवाज, उनके आश्रमों का डिजिटल भ्रमण व उनके पसंदीदा भजनों का संग्रह होगा।

अमेरीका और कनाडा के बीच समझौता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका और कनाडा के बीच 30 सितम्बर 2018 को नाफ्टा समझौते (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते) को लेकर सहमति बन गई. इस समझौते में मैक्सिको भी शामिल है.

नया समझौता 'यूनाइटेड स्टेट्स–मैक्सिको–कनाडा संधि' (यूएसएमसीए) करीब 25 साल पुरानी 'उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संधि' (नाफ्टा) की जगह लेगा. अमेरिका नवंबर 2018 के अंत में कनाडा और मैक्सिको के साथ नाफ्टा समझौता की जगह नई डील पर हस्ताक्षर करेगा जिसके बाद उसे स्वीकृति के लिए अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जाएगा.।

समझौता से संबंधित मुख्य तथ्य:

यह समझौता अमेरिका कनाडा और मेक्सिको तीनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील के कारण तीनों देशों के बीच व्यापार और कर नियमों में बड़ी छूट मिलती है। मेक्सिको और अमेरिका के बीच अगस्त में नाफ्टा डील पर बात बन गई थी, लेकिन कनाडा इससे बाहर था। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ नाफ्टा व्यापार समझौता पूरी दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक माना जाता है। इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया। तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समझौते में कई तरह की छूट दी गई है।

विश्व में पहली बार टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों के जन्म में सफलता हासिल की गई. ये शेर शावक कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए हैं। शेर के शावकों की यह जोड़ी विश्व की पहली ऐसी जोड़ी है. प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अफ्रीकी शेरनियों के प्रजनन तंत्र पर शोध कर रहे हैं. इन वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक की मदद से इन शावकों को जन्म देनें में सफलता

भारत और मोरक्को ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई सेवा समझौता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत व मोरक्को ने 19 सितंबर 2018 को संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस आधुनिक समझौते से दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विगत वर्षों में तीन बार बैठकें कीं. इस दौरान दोनों देशों के बीच बाजारों को उदार बनाने और वर्तमान हवाई सेवा समझौते का अद्यतन करने की दिशा में प्रयास किए गए। दोनों पक्षों ने कानूनी एवं तकनीकी बाधाएं दूर की और इसके साथ ही दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते का आधुनिक मसौदा तैयार करने पर सहमति जताई. इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने–अपने यहां की सरकार से हवाई सेवा समझौते के स्वीकृत मसौदे पर मंजूरी प्राप्त की। इस समझौते पर पर्यटन, हवाई परिवहन, हस्तशिल्प और सामाजिक अर्थव्यवस्था मंत्री मोहम्मद साजिद की भारत यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं.

मोरक्को पक्ष की ओर से मोहम्मद साजिद और भारतीय पक्ष की ओर से केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संशोधित हवाई सेवा समझौताः

इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत एवं मोरक्को के बीचे हवाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके साथ ही दोनों देशों की एयरलाइंस आपस में कोड को साझा कर सकेंगी। इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने में अब और भी अधिक आजादी संभव होगी। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में इन घटनाक्रमों या समझौतों से एक देश के लोगों को दूसरे देश की यात्रा करने में सहूलियत होगी जिससे पारस्परिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और ज्यादा सुदृढ़ होंगे।

पीएनबी घोटाला - नीरव और उसके परिजन की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ भारत समेत पांच देशों में कार्रवाई की । इस दौरान 637 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक खाते अटैच किए गए । ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई, लंदन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और न्यूयॉर्क में की गई । उधर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि हम नीरव जैसे लोगों को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं।

ईडी ने न्यूयॉर्क में 216 करोड़ रुपए की कीमत का अपार्टमेंट सीज किया । यह संपत्ति इचाका ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई । नीरव की पत्नी एमी इस ट्रस्ट से जुड़ी है ।

फेसबुक को बड़ा झटका, आधे से ज्यादा युवाओं ने फोन से डिलीट किया ऐप

सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक को एक और बड़ा झटका लगा है। कैम्ब्रिज ऐनालिटिका डाटा लीक विवाद के बाद से युवाओं के बीच फेसबुक की लोकप्रियता में कमी आई है। अमेरिकी Pew survey के मुताबिक, 18 से 29 वर्ष उम्र के बीच के ज्यादातर युवाओं ने फेसबुक ऐप को अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दिया है या फिर फेसबुक से ब्रेक ले लिया है। करीब 3,400 अमेरिकी युवाओं के बीच किए गए सर्वे के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करने वाले युवाओं में से 26 फीसद युवाओं ने फेसबुक ऐप को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। जबकि, 42 फीसद युवाओं ने फेसबुक से फिलहाल ब्रेक ले लिया है यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि, इस सर्वे में फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम, वॉटसऐप और मैसेंजर ऐप यूजर्स शामिल नहीं है। विदेशों में ये ऐप्स भी काफी लोकप्रिय है। फेसबुक के प्रति युवाओं की उदासीनता इस साल के शुरुआत में कैम्ब्रिज ऐनालिटिका विवाद के बाद से आई है। Pew survey ने इस साल मई और जून के महीने में 3,400 से ज्यादा अमेरिकी यूजर्स के बीच सर्वे किया है। इस सर्वे में करीब 54 फीसद युवाओं ने अपने फेसबुक में प्राइवेसी सेटिंग्स में भी बदलाव किया है।

जस्टिस सूर्यकांत बने हिमाचल हाईकोर्ट के 23वें मुख्य न्यायाधीश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 23वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अप्रैल, 2017 से जस्टिस संजय करोल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। हरियाणा के जिला हिसार में मध्यवर्गीय परिवार में 10 फरवरी, 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1977 में गांव के स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की। वर्ष 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज से स्नातक की। अब जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे।

बहुपक्षवाद, यूएनएससी सुधार के लिये जी-4 देशों की बैठक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के संबोधन में बहुपक्षवाद की निंदा किये जाने के कुछ समय बाद हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्राज़ील, जापान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों–क्रमशः अलॉयसियो नून्स फेरेरा, तारो कोनो तथा हीको मास की जी–4 बैठक की मेज़बानी की।

इस बैठक में भारत और अन्य जी–4 देशों ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रारंभिक सुधार किये जाने की मांग की। जी–4 देशों के मंत्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 21वीं शताब्दी की समकालीन ज़रूरतों के लिये संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता हेतु सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। जी–4 के मंत्रियों ने व्यक्त किया कि सुरक्षा परिषद सुधार का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के भारी बहुमत के बावजूद, 2009 में शुरू हुई बातचीत ने 10 वर्षों में वास्तविक प्रगति नहीं की है। इस बैठक के दौरान जी–4 देशों के मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद सुधार की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और उन्होंने अपने देशों के संबंधित अधिकारियों को सुधार कार्य आगे बढ़ाने के तरीके पर विचार करने के लिये काम करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र के बजट में पाँचवें हिस्से का योगदान करते हैं जबकि जी – 4 देशों में विश्व की आबादी का पाँचवाँ हिस्सा रहता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018: हरियाणा को मिला सर्वोच्च पुरस्कार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018

हरियाणा को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018' के तहत 02 अक्टूबर 2018 को सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पुरस्कार 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018' के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च स्थान के पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के छह जिलों में हरियाणा के तीन जिले गुरूग्राम, करनाल और रेवाड़ी भी शामिल हैं। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने हरियाणा के उक्त तीन जिलों को सर्वोच्च जिला श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र जून 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं। राज्य के सभी शहरी क्षेत्र भी अक्टूबर 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं। वर्ष 2019 तक हरियाणा के सभी गावों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अन्य पुरस्कार

- महाराष्ट्र के सतारा जिले को कुल 97.90 अंक मिले है और यह जिला देश में पहले स्थान पर रहा है।
- रेवाड़ी जिले को 97.62 अंक प्राप्त हुए तथा यह दूसरे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त हरियाणा के गुरुग्राम और करनाल को भी टॉप छह जिलों में स्थान हासिल हुआ।
- स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018 में पुणे के सिंबॉयसिस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है।

सरकार ने की भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विघटन की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कामकाज की निगरानी करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षण समिति के अचानक इस्तीफा देने के बाद सरकार ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक इस 100 सदस्यीय परिषद के वर्तमान स्वरूप को भंग कर दिया।

नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल की अध्यक्षता वाली समिति ने जुलाई माह में परिषद पर आरोप लगाते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा था कि, "एमसीआई अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। मंत्रालय को या तो इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिये या सर्वोच्च न्यायालय को इससे अवगत कराया जाना चाहिये।" बाद में, पॉल ने एमसीआई के खिलाफ जाँच आयोग की मांग करते हुए मंत्रालय को फिर से पत्र लिखा। इसके बाद पाँच सदस्यीय समिति ने इस्तीफा दे दिया। इस समिति में वी.के. पॉल के अतिरिक्त दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया; एम्स में प्रोफेसर और एंडोक्राइनोलॉजी के प्रमुख निखिल टंडन; चंडीगढ़ में पीजीआई के निदेशक जगत राम तथा बंगलूरू में NIMHANS के निदेशक बीएन गंगाधरन शामिल थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पूरी समिति द्वारा विरोधस्वरूप इस्तीफा दिये जाने के बाद मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता। जिससे मंत्रालय को सर्वोच्च न्यायालय की और अधिक आलोचना झेलनी पड़ती।

इसलिये एमसीआई को भंग करने का निर्णय लिया गया और पर्यवेक्षण समिति के पाँच सदस्यों को नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1933 के तहत स्थापित इस परिषद का कार्य एक मेडिकल पंजीकरण और नैतिक निरीक्षण करना था।

विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर 3.9 प्रतिशत किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने वैश्विक व्यापार वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा दिया है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, बाज़ार की तंग क्रेडिट स्थितियों के साथ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव की वज़ह से 2018 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3.9 प्रतिशत और 2019 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2018 के लिये नया पूर्वानुमान, डब्ल्यूटीओ द्वारा 12 अप्रैल को घोषित किये गए पूर्वानुमान 4.4 प्रतिशत से कम है। लेकिन नया पूर्वानुमान उस समय के निर्दिष्ट अनुमान 3.1 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के बीच ही है। हालाँकि 2018 में व्यापार वृद्धि अब 3.4 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत की सीमा के बीच रहेगी। व्यापार वृद्धि मज़बूत होने के बावजूद यह गिरावट प्रमुख व्यापार भागीदारों के बीच बढ़ते तनाव को प्रतिबिंबित करती है।

विश्व व्यापार संगठन

- विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर–सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में मारकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था। सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।
- वर्तमान में इसके 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया।

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 01 अक्टूबर, 2018 को भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इस पद पर पहुंचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं, उनसे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी आईएमएफ में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं। गीता गोपीनाथ की नियुक्ति की घोषणा करते हुए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहां कि "गोपीनाथ दुनिया के उत्कृष्ट अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड बेहद शानदार है और उन्हें वृहद अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल है।

गीता गोपीनाथ ने अपनी एमए की डिग्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से हासिल की है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र की जॉन ज्वानस्त्रा प्रोफेसर हैं। गीता गोपीनाथ केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी हैं और हार्वर्ड में प्रकाशित उनके जीवन परिचय के मुताबिक, इस मानद पद पर उनकी नियुक्ति साल 2016 में हुई थी और उन्हें मुख्य सचिव का रैंक दिया गया है. गीता अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू की सह–संपादक और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (एनबीइआर) में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मैक्रोइकोनॉमिक की सह–निदेशक भी रहीं।

गीता गोपीनाथ का कार्यभार

गीता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के जिस विभाग की निदेशक नियुक्त की गई हैं, उसका कार्यभार संस्था में सबसे अहम माना जाता है। आईएमएफ का यह अनुसंधान विभाग विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं पर अध्ययन करके सदस्य देशों के लिए जरूरी नीतियां तैयार करता है, साथ ही साथ उन मुद्दों पर रिसर्च को अंजाम देता है जो आईएमएफ के लिए अहम होते हैं।

यूआईडीएआई: टेलिकॉम कंपनियां दो हफ्तों में जमा करें आधार डीलिंक करने का प्लान

आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिन की मोहलत दी है। यूआईडीएआई ने कहा है कि पहले ईकेवाईसी के जरिए जारी सिम कार्ड के बारे में जल्द फैसला ले। कंपनियां कैसे आधार को डीलिंक करेंगी, इसके बारे में जल्द उसे बताना होगा।

इन कंपनियों को भेजा सर्कुलर

यूआईडीएआई ने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया सहित अन्य कंपनियों को सर्कुलर भेज कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आधार कानून के सेक्शन 57 को निरस्त कर दिया था। इस सेक्शन में कंपनियों को 12 संख्या वाले आधार नंबर को ईकेवाईसी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

2016 में आरबीआई ने दिया था निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2016 में ओटीपी के जरिए ईकेवाईसी करने का निर्देश दिया था। आरबीआई ने तब अपने आदेश में बैंकों को कहा था कि वो ओटीपी के जरिए ग्राहकों की सहमति से ईकेवाईसी कर सकते हैं। हालांकि ईकेवाईसी कराने वाले ग्राहक एक साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने हर उम्र की महिलाओं के लिये खोले सबरीमाला मंदिर के दरवाज़े

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 4:1 के बहुमत से हुए फैसले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि हर उम्र की महिलाएँ अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वर्ष 1991 में दिये गए उस फैसले को भी निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकना असंवैधानिक नहीं है। सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके लिये कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं। केरल के 'यंग लॉयर्स एसोसिएशन' ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में जनहित याचिका दायर की थी। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिये आते हैं, इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिये बंद रहता है। भगवान

अयप्पा के भक्तों के लिये मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिये उस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है।

नीति आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य सतत विकास फ्रेमवर्क पर समझौता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में तीन आधारभूत परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इनमें भारत–बांग्लादेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं – भरमार (बांग्लादेश)–बहरामपुर (भारत) अंतरसंपर्क के जरिए भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, अखौरा–अगरतला रेल लिंक और बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा शाहबाजपुर खंड का पुनरुद्धार योजना।

समयपूर्व लोकसभा और विधानसभा भंग होते ही लागू होगी आचार संहिता: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग द्वारा 27 सितम्बर 2018 को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी विधानसभा के समय से पहले भंग हो जाने पर राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और यह नई सरकार के गठन तक जारी रहेगी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के दौरान लागू की जाने वाली आचार सहिंता को लेकर एक बड़ा फैसला ह। इस आचार सहिंता में राज्य की कार्यवाहक सरकार नयी योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है। कुछ सप्ताह पहले तेलंगाना में विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल (जून 2019) पूरा होने से पहले ही भंग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। इसके तहत तेलंगाना में भी आयोग द्वारा यह स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ ही आचार संहिता लागू मानी जायेगी।

केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2018 को नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक टेलीकॉम सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश और 40 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करना है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में नेट निरपेक्षता पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल विषयवस्तु के साथ कोई भेदभाव न करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक: आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com RNI Reference No. 1328500

Upbringing Aspirational Districts - NITI AYOG's Initiative – Perspective and Challenges

There has been significant thought process on minimising developmental gaps and bringing equilibrium in order to address the issues arising out of regional imbalances in the country. The erstwhile Planning Commission had come forward with the initiative of Integrated Decentralised District Planning (IDDP) process initially in the backward districts of the country which was to be replicated across country. The process was defined very meticulously and had it been implemented religiously, it would have brought the change on ground. It was implemented by the Ministry of Panchayati Raj, Govt of India through the respective state government(s) with facilitation support of some Technical Support Institution (TSI).

No doubt the conceptual framework of the process was defined well but jeopardised for some implementation bottlenecks as the dilution of implementing all good ideas has been experienced in majority of the cases.

IIRD also had an opportunity to contribute as Technical Support Institution (TSI) in Chamba District in converting vertical planning into horizontal one. The exercise was of great learning and experience. The process as outlined by the manual published by the Ministry of Panchayati Raj, Govt. of India was tried to be adopted in a fair and impactful manner. Many senior officers of the district also volunteered enthusiastically and many days and even nights were utilised for brainstorming, discussion, planning and capacity building exercises during 12th Five Year Plan period. The specific process adopted was as under:

- Identification of relevant enthusiastic as well as resourceful people including district level officers and Notified District Planning Team
- Notified Block and Panchayat Planning Teams
- Capacity Building on the Vison of Horizontal Planning and the Complete Conversion Process.
- Stakeholders Consultation at different levels.
- Prepared Stalk Taking Report with rich data collected from various sources.
- Worked out Financial Envelopes applicable for different tiers or planning units.
- Carried out Sectoral Planning Process in due consultation with the available experts.
- Developed 15 Years District Vision Document comprising 18 Sectors
- Facilitated in Annual Plan Preparations
- Shared some recommendations with the Govt. for policy modification

With the intensive exercises with a number of stakeholders and government officers and representatives, the 15 Years Vision Document was prepared for 18 sectors with identification of three prioritised and potential sectors.

For implementation of the same, some policy level interventions were to be initiated by the state government and the detailed recommendations were shared with the state government and tried to have discussion at different levels of the Department of Panchayati Raj, Govt of Himachal Pradesh as well.

As the recommendations were more pertaining to notify planning and financial benchmarks for the different levels of the three tier system to avoid duplication and triplication of efforts, the idea never got seriousness at the government level hence remained pending for indefinite period. Gradually, the efforts put in towards converting vertical planning into horizontal planning as well as concentrating towards achieving Developmental Vision of the district gradually got jeopardised.

Recently, the NITI AYOG's initiative on Aspirational District is again a welcoming step in the direction for bringing up the backward districts more or less on the similar analogy. Before making any comparative analysis between the earlier Integrated Decentralised District Planning Process and the present initiative on Aspirational Districts, it seems worth to have mention of the likely challenges to see the tangible results in the Aspirational Districts. A few of the likely challenges as outlines as below:

Challenges, the Aspirational Districts may face and Some Suggestions:

In order to see tangible change in the Aspirational Districts, the challenges encountered during IDDP process need to be overcome with revised strategic approaches. Some concerns and suggestions are outlined below to make this initiative more impactful.

1. Convergence is a grey area

In almost all mission mode projects, there has been convergence components which hardly takes place because of the reasons that (a) the planning timelines of every scheme is different and hardly can anything be converged; (b) the schematic guidelines for each programme are also variable which may not become feasible many a times; (c) the funds spending modalities too may vary and mismatch when needs to be converged; (d) the paucity of funds also cannot be overlooked.

Accordingly, if there are no separate and exclusive allocation of funds for bridging critical gaps, mere convergence may not work.

2. Seriousness of the States

The approach of the state governments usually remains to implement the central scheme in routine manner. The Aspirant Districts until adopted in a mission mode for holistic development, cannot achieve the envisaged outcome. The state governments are expected to create seriousness for the same and treat this as one of the key priorities.

3. Additional Responsibility of Collector will dilute the Initiative

The position of the District Collector in India is most powerful with N number of responsibilities and mandates. The time required for district planning and implementing the programmes like Aspirational District Initiatives need exclusive and senior officer atleast equivalent to Joint Secretary of GoI to be deputed in the district for minimum 5 years' period with missionary spirit. The additionality of the task will make it additional always but not the exclusive.

4. Planning & Financial Benchmarks need corrective measures

The local representatives i.e. elected people in three tier system of our democratic set up have been demanding discretionary powers to make financial announcements like ministers for long. The existing guidelines nowhere restrict the member of Zila Parishad to opt for the scheme in particular Gram Panchayat Ward equivalent to the scheme being undertaken by the Ward Member. Because the planning benchmarks are not set up, there cannot be deny from duplication and triplication of the efforts. Similarly, the higher level representative can propose scheme / project equivalent to the same being proposed by the lowest level representative in the pyramid of democracy.

5. This requires Missionary Spirit with Innovations

Upbringing Aspirant Districts within given timeline cannot be treated as routine affairs, but needs to be taken up with missionary spirit. A number of innovations in procedures, processes and implementation mechanism need to be evolved just ensure tangible results in a shortest time span.

6. Technical Support Institutions to Report to GoI:

Only the experienced and passionate TSIs need to be engaged with better resource provisions and time based outcome indicators. Their engagements need to be finalised by the GoI with reporting to the GoI only. The reporting to the state will dilute the likely impact.

7. Horizontal Planning Cannot Be Ignored:

The optimum utilisation of the resources can be ascertained if the horizontal planning is introduced as many agencies have been spending resources on the similar affairs without any information amongst them.

8. Encouragement of Technical Institutions:

The Technical Institutions willing to contribute for the development of the district or willing to adopt any district need to be encouraged for achieving defined developmental milestones within specified timelines. This may differentiate the speed of actions at different levels.

Sectoral Vision Document- Sample Exercise Made for Chamba District During 2011.
Agriculture

Broad vision – Evolving a practice which promotes sustainable agriculture with focus on food crops with higher yield and subsequent marketing facilities especially benefiting small and marginal farmers.

Analysis of infrastructure

The district has a strong network of agricultural institutions. The main agricultural development institutions prevalent in the district are – The Krishi Vigyan Kendra (Horticulture), Dy. Director (Agri), Research Sub Station (CSKHPKV). Six seed multiplication farms are functioning at Bhanota, Rajpura, Bhagat, Thullet, Ahla and Dharwas.

University of Agriculture Palampur has prepared a plan for the development of agriculture in the district which should be implemented religiously.

Analysis of performance

The total cultivated area in the district was 59.3 thousand hectares according to 1991-92 survey (66259 Ha in 2010). Out of the total geographical area of 6,92,419 hectares, the cultivated area is only 41886 hectares.

Maize is the main crop of the Kharif season and potato and paddy are also sown, where the conditions so permit. Wheat and barley are the major Rabi crops. Millets and coarse cereals like Ogla, Kangni, Cheeney, Chilai and Bathu constitute important crops of the cold region of Bharmaur and Pangi where maize is not sown during the Kharif.

The area under maize and wheat as well as their yield increased in the district though was unpredictable and uncertain over the years. On the other hand the area under paddy, barley and pulses declined considerably due to allocation of more irrigated area to vegetable crops and hence marginalization of the three crops in hill farming. The combined yield of all food grains showed marked increase.

Peas and tomato are the major vegetable crops collectively accounting for about 52 percent of the total area and 45 percent of the total vegetable production apart from potato and cabbage in the district. Most of the production goes towards catering local needs. The area and production of vegetables in the district has increased steadily with the cultivation of off-season vegetable crops by virtue of implementation of minor irrigation schemes in different parts of the state.

The availability of cultivable land decreases drastically from low to high hills. In the blocks like Bharmaur, Tissa and Salooni, the availability of arable land is limited due to undulating topography and hilly terrains.

There are number of problems in different categories of land. The major problems are:

- Undulating topography leading to more soil erosion and land slides
- Lack of sufficient tree cover in barren lands, infestation of pasture with obnoxious weeds,
- Uncontrolled grazing,
- Lack of improved grasses and fodder trees.

There is very limited market surplus in cereals, pulses and oilseeds as major proportion of these commodities is consumed. Similar pattern was observed in milk also. However, there is substantial surplus of fruit and vegetables in all the blocks. In case of vegetables, out of total production of 1,15,347 quintals, 52,074 quintals formed the marketed surplus. Similarly, in fruit, total production was estimated at 2,00,056 quintals out of which as high as 1,80,654 quintals was marketed.

Ongoing Schemes of Agricultural Development:

- Crop Improvement Programme for Cereals
- Schemes for Mechanization
- Schemes for balanced and integrated nutrients management
- Schemes for innovative agricultural extension
- Schemes for farm women empowerment-a village based training
- Integrated Schemes of oilseeds, pulses, palm oil and maize

Vision

All cultivable and fallow land to be brought under cultivation across the district in the next ten years with the help of organic farming and other soil rejuvenation measures.

Monkey menace tackled in the next five years by taking various steps like sterilization, fruit plants in jungles etc.
High yielding varieties of cereals and pulses introduced in the district in the next five years with special emphasis on maize which is quite popular in the state.

- Diversification of crops taken up as a major strategy in the next 10-15 years.
- The area under irrigation increased by another 25% in the next five years.
- Mechanised agriculture practiced in suitable pockets of the district in the next 5-10 years.
- Modern means of marketing set up with investments from the private sector in the next 5-10 years.

Strategies

- Converting / Developing 2,085 hectares of culturable waste and 5,523 hectares of fallow land.
- Increase in substantial investment on reclamation, fencing/bunding and development of irrigation
- Conservation of the vast forest and pasture lands.
- Establish primary market sub-yards in potential areas (preferably in all blocks) and integrate these with the principal market (to be set up) to provide local market outlets and remunerative prices to producers.
- Encouraging the cultivation and agro-processing of Buck wheat and amaranths (which are not only nutritious but highly durable crops).
- Filling up of vacant positions / Recruitment of new and trained personnel to handle the implementation of the agricultural plan in the district.

Outcomes:

- Productivity of maize, paddy, pulses, barley, wheat and oilseeds increased.
- A sound conservation and sustainable exploration strategy in place to protect and tap the rich repository of timber trees, walnuts, wild apricot, temperate grasses and high value medicinal herbs.
- Agro-based industries are promoted across the district and a strong agricultural marketing system developed.
- Productivity improvements, diversification of area, area expansion in high yielding varieties, increasing cropping intensity, improvement in seed replacement ratio, use of integrated pest management, integrated nutrient management, water use efficiency through micro-irrigation schemes, popularizing organic farming, use of farm mechanization, improvement in horticultural productivity, soil and water management which includes construction of farm ponds.

Outcomes matrix:

Strategies	Activities	Challenges
Outcome: An effective land reform policy in place with focus on reclaiming unused/barren/fallow land for agriculture and allied purposes.		
Joint decision making by the Departments of Land Resources, Agriculture, Soil and Water Conservation, Horticulture, Fisheries, Forests and PWD in preparing a policy note on land use pattern in the district (State).	**Complete mapping of current land use pattern and the extent of unused/barren/fallow land which can be claimed for agricultural purposes and thus increase cultivable area.**	**Departments like Forests and PWD might disagree to a joint policy owing to their respective landuse restrictions.**
	Mass mobilization to discourage division of land and incentivising land unification by providing better agricultural inputs / subsidies etc.	**This might be time taking and somewhere very difficult to convince the local population.**
Increasing investments on reclamation, fencing / bunding and development of irrigation.	**-Allocate additional resources by pooling in State and Central sponsored funds and also bank loans.**	**Pooling of funds might be difficult due to different funding regimes and cycles. -Promote watershed development activities in catchment areas to enhance soil moisture and small scale irrigation.**
So on for all outcomes………		

Dr. L.C. Sharma
MD IIRD, Shimla
md@iirdshimla.org

प्रिय पाठकों द रीव टाइम्स में इस अंक से हम आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराने जा रहे हैं। इस श्रृखंला को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीणों को उन सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना है जिनका लाभ उठाकर वे अपना और अपने गांव का विकास कर सकते हैं। इसी अंक में हम आपको बता रहे हैं भारत सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के बारे में...

आयुष्मान भारत योजना

हमारे देश में बीमारी के इलाज का खर्चा पूरे परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय होता है। साथ ही, चिकित्सा का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अनेक मामलों में इलाज के लिए लोगों को उधार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी है। पूरे परिवार को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर परिवार गरीब है, पैसे के अभाव की वजह से कई बार सही इलाज भी नहीं करा पाते। इसी परेशानी पर विचार करते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। तकरीबन 50 करोड़ भारतीयों को इस योजना से लाभ होगा।

यह इंश्योरेंस सेवासुविधा बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जा रही है परिवारों के चयन Socio & Economic Caste Consensus 2011 के अनुसार किया गया है। यह योजना 25 सितम्बर, 2018 से शुरू हो गई है आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम 10.74 करोड़ गरीब और जरुरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ

50 करोड़ भारतीयों को सीधा फायदा

‘निजी और सरकारी अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज
हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संभव
कुछ भी प्रीमियम नहीं देना होगा, पूरे देश में कहीं भी करा सकेंगे इलाज

परिवार में सदस्यों पर कोई सीमा नहीं, पूरे परिवार को मिलेगा फायदा आवेदन करने की जरुरत नहीं, अगर पात्र हैं तो अपने आप नाम लिस्ट में आ जाएगा। आपके परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर (स्वास्थ्य बीमा) मिलेगा। आपके परिवार के सभी लोग शामिल होंगे। इस बीमा के तहत आपको अस्पताल में दाखिला लेने पर (hospitalization) आपके इलाज का खर्चा इंश्योरेंस प्लान उठाएगा। आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होगा। दवाईयों, डॉक्टर से परामर्श (consultation), डायग्नोस्टिक टेस्ट, सर्जरी इत्यादि, किसी का भी खर्चा आपको नहीं देना होगा। यह सारे खर्चे इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर हैं। यह पालिसी पूरी तरह कैशलेस (Cashless) है। आपको अपनी जेब से एक भी पैसा देनी की जरुरत नहीं है। आपको प्रीमियम भुगतान करने की जरुरत नहीं है। आपके लिए यह सुविधा बिलकुल मुफ्त है। योजना की मदद से आप अपने परिवार को बेहतर चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं।

अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उस बीमारी के इलाज के लिए भी भुगतान इंश्योरेंस पालिसी से होगा।

देश के किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज

आप इलाज के लिए पूरे देश के किसी से सरकारी अस्पताल या सूची में सम्मलित निजी अस्पतालों (Empanelled Private Hospitals) में जा सकते हैं। आपको हर जगह मुफ्त इलाज मिलेगा। ध्यान दें आपको अपने शहर के अस्पताल में जाना जरूरी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भरती होने से पहले के और बाद के खर्चे (Pre & Hospitalization and post & hospitalization expenses) का भुगतान भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी।

कैसे लें योजना का लाभ

आयुष्मान भारत योजना में एनरोल (enrollment) करने की कोई जरुरत नहीं हैं। इसका मतलब आपको योजना के तहत लाभ पाने के लिए कोई आवेदन करने की जरुरत नहीं है। अगर आप योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं, तो आपका नाम अपने आप लाभार्थियों को सूची में अपने आप आ जाएगा। ध्यान दें इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। केवल गरीब परिवारों को ही सुविधा का लाभ मिलेगा।

ऐसे चैक करें अपनी पात्रता

अगर आपका नाम आयुष्मान भारत योजना की सूची में है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आप आयुष्मान भारत की वेबसाइट (https://mera-pmjay-gov-in/search) पर जा कर चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जा कर आप लाभार्थियों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप नाम, जगह, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर इत्यादि पर ढूंढ सकते हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्वाथ्य बीमा योजना (RSBY) में शामिल थे, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाएँ (https://mera-pmjay-gov-in/search/) अपना मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल पर ओटीपी (one time password) आएगा। उसके बाद अगले पेज पर आप अपने नाम को ढूंढ सकते हैं।

नाम	
मोबाइल नंबर (mobile number)	
राशन कार्ड नंबर (Ration card number)	

आएगी चिट्ठी

सरकार सही लाभार्थियों को चिट्ठी भी भेजेगी जिसमें उनके परिवार और योजना की पक्की जानकारी होगी।

आयुष्मान भारत योजना के लिए योग्यता मानदंड

ग्रामीण क्षेत्रों में (in Rural Areas) एक कमरे के कच्चे घरों में रहने वाले लोग, जिस परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच में कोई सदस्य न हो, स्त्री प्रधान घरों में , जहां 16–59 आयु वर्ग में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, जिन परिवारों में एक विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, SC/ST परिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति), जिन परिवारों की पास कोई जमीन नहीं है, और मजदूरी करते हैं, गरीब बेसहारा लोग, जो भिक्षा पर जीवन बिताते हैं, जो मल उठाते हैं, प्राचीन जनजातीय समूह, जो पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे।

शहरी क्षेत्रों में (in Urban Areas) सरकार ने श्रमिकों की इन 11 व्यावसायिक श्रेणियों की एक सूची बनाई है, जो सूची में अपने आप शामिल हो जायेंगे। कूड़ा उठाने वाले (Rag Picker), भिखारी (Beggar) लोगों के घरों में काम करने वाले, सड़कों पर काम कर रहे मोची या अन्य विक्रेता,मजदूर, मिस्त्री,निर्माण कार्यकर्ता , प्लम्बर , मेसन पेंट, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड , कुली इत्यादि,स्वीपर, स्वच्छता कार्यकर्ता , माली, गृह आधारित कर्मचारी , कारीगर, हस्तशिल्प कार्यकर्ता , दर्जी, ट्रांसपोर्ट कार्यकर्ता , चालक , कंडक्टर , ड्राइवर और चालक कार्ट खींचने वाला, रिक्शा खींचने वाला सहायक,छोटे प्रतिष्ठानों, दुकानों में काम करने वाले, सहायक, वेटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, असेंबलर, मरम्मत कार्यकर्ता, वाशर–मैन, चौकीदार

आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा?

आपको किसी भी तरह के आवेदन करने की जरुरत नहीं है। जब आप अस्पताल जायेंगे, तब आपको एक पहचान पत्र ले कर जाना होगा (आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि)। अस्पताल में चेक कर लिया जाएगा की आप आयुषमान योजाना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं या नहीं। उसके बाद आप फ्री में इलाज पा सकते हैं।

आधार नही तो एक ही बार मिलेगा लाभ

ध्यान दें बिना आधार कार्ड के आप केवल एक बार ही इलाज का लाभ ले सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा की आप आधार कार्ड बनवा लें। आप अपने परिवारों के सदस्यों को आयुष्मान योजना में जोड़ सकते हैं? अगर आपका नाम सूची में है, तो अपने परिवार के नए सदस्यों को अपनी पालिसी में जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा। राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम, Birth Certificate (जन्म प्रमाण पत्र), मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate)

चोरों से रहे सावधान

ध्यान दें कुछ धोखेबाज लोग या वेबसाइट आपको आश्वासन देंगे की वह आपसे पैसे लेकर आपको इस योजना का लाभ दिला सकते हैंद्य ऐसे लोगों से बचें। अगर आपका नाम लाभारती सूची (beneficiary list) में है, तो आपको आयुषमान भारत का लाभ लेने के लिए एक रूपया भी खर्च करने की जरुरत नहीं है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप कोई लाभ नहीं मिलेगा।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस हिसाब से ये लोग आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है। परिवार जिसके पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और फिशिंग बोट है। वो जिसके पास 3 पहिया और 4 पहिया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट (ट्रैक्टर) है। परिवार जिसके पास 50 हजार रुपए से ज्यादा की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है। परिवार जिसका सदस्य सरकारी नौकरी करता है। परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड है। परिवार में अगर घर का कोई सदस्य 10 हजार रुपए से अधिक कमाता है। ये सभी पात्र नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले परिवार को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। परिवार जो प्रोफेशनल टैक्स भरता है। ऐसे परिवार जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे का पक्की दीवार और छत वाला मकान है। जिसके पास रेफ्रिजरेटर है। जिसके पास लैंडलाइन फोन है। जिसके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा 1 सिंचाई यंत्र के साथ सिंचित भूमि है। जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा 2 फसल सीजन वाली सिंचित भूमि है। जिसके पास एक सिंचाई यंत्र के साथ 7.5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है। ये लोग भी इसके पात्र नहीं है।

आयुष्मान भारत योजना का हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट लॉन्च, ऐसे चेक करें अपनी पात्रता ऐसे कई परिवार हैं जो सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में बाहर हो गए थे लेकिन आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में मौजूद हैं। इन परिवारों को बाहर करने के लिए कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। इसलिए अगर आपका नाम पात्रता सूची में नहीं है तो इसकी असली वजह है आपका नाम सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 में नहीं होना है।

अन्य जानकारी आयुष्मान भारत टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 14555

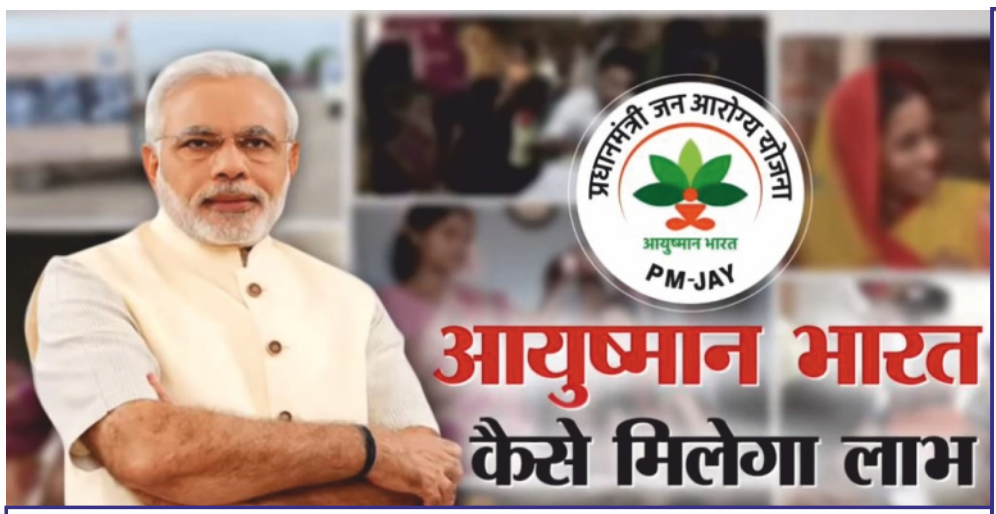

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हिमाचल प्रदेश में

- प्रदेश के लगभग 22 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।
- लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का निशुल्क उपचार।
- पूरे देश में सरकारी अथवा प्राईवेट पंजीकृत अस्पताल में इजाज की सुविधा।
- प्रदेश में अब तक सरकारी तथा प्राइवेट 175 अस्पताल पंजीकृत।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चयनित परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र।

पंजीकृत अस्पताल में इलाज के समय अपना राशन कार्ड/आधर कार्ड अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड साथ लेकर जाएँ

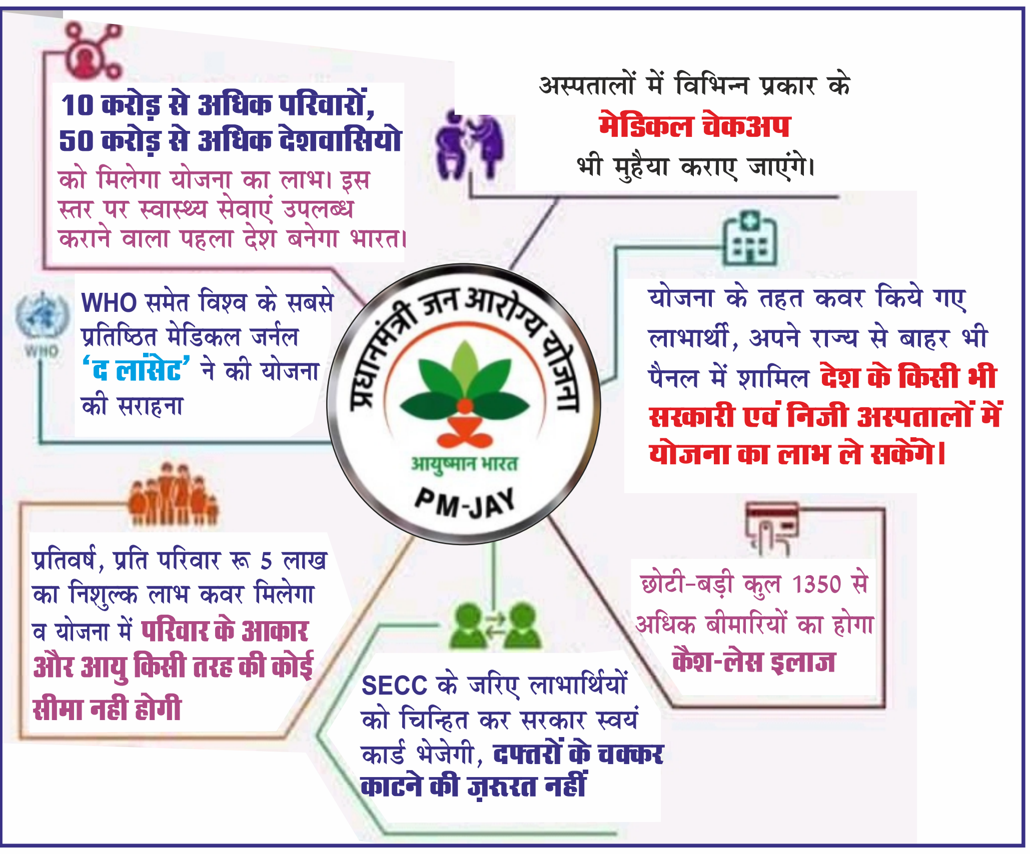

Advertorial

मिशन रीव में 'रीव को-ऑर्डिनेटर' के पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं

सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत होगी, जो अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। मिशन रीव - जहां आपको मिलेगा अपने घर के पास ही काम/ रोज़गार के साधन। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहते हुए अपने गाँव के उत्थान के लिए काम करेंगे। अगर आप में है समाज सेवा, अपने गाँव को सशक्त, स्वाबलमबी, सुविधा सम्पन्न बनाने का जूनून और बेहतर रोजगार को अपनाने की चाहत तो आइये जुड़िये अनोखे और अद्वितीय मिशन रीव से।

अनिवार्य योग्यताएं :

किसी भी विषय मे स्नातक अथवा 10+2 के बाद डिप्लोमा धारक
बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान, एम.एस. एक्सेल तथा एम.एस. वर्ड
ई-मेल और इंटरनेट का ज्ञान
लोगों को एकत्रित करने की (Community Mobilization)
क्षमता, सेल्स तथा मार्केटिंग करने की क्षमता

आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
आवेदन करने से पूर्व इन बातों का रखें ध्यान

- आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष की होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक या समकक्ष। 12वीं के बाद डिप्लोमा धारक का आवेदन भी मान्य है
- आवेदन की प्रकिया विस्तृत तथा ऑनलाइन ही है। इसके लिए आवेदक के पास वैब कैम से लैस कंप्यूटर/लैपटॉप होना अनिवार्य है। हालांकि कुछ प्रक्रिया एंड्रायड मोबाइल फोन से भी पूरी की जा सकती है।
- भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल recruitment.missionriev.in है। तथा यह मोजिला ब्राऊजर में ही बिना रूकावट से चलेगा। अतः आवेदक को आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि उसके एंड्रायड मोबाइल/कंप्यूटर/लैपटॉप पर मोजिला ब्राऊजर क्रियाशील हो।
- आवेदन करने की प्रकिया में 10 चरण हैं। आवेदक को प्रत्येक चरण को पूरा करना अनिवार्य है। इसके बारे में आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ई–मेल पर सूचना मिलती रहेगी। अतः सूचना प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टल पर पंजीकृत नंबर व ई–मेल हमेशा सक्रिय रहे।
- पोर्टल पर जाते ही 'टेक अ टूर' विडियो प्रसारित होगा। इस विडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको यह आभास हो जाएगा कि जिस कार्य को करने के लिए आप आवेदन करने वाले हैं उसे करने में आप कितने सक्षम हैं। यदि आपको लगता है कि विडियो में दर्शाए गए कार्य को आप नहीं करना चाहते या इसे करने में सक्षम नहीं तो आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विडियो के मुताबिक खुद को कार्य करने में सक्षम पाते हैं तो विडियो समाप्त होने के बाद उसे बंद कर आगे बढ़े। आगे जाते ही आपके सामने आवेदन का विकल्प आएगा। एप्लाइ बटन पर ओके करते ही आपके सामने फार्म खुल जाएगा। फार्म के मुताबिक पूरा फार्म भरने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपको आवदेन शुल्क जो मात्र 600 रूपये ऑनलाइन अदा करना है। यह शुल्क नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से जमा किया जा सकता है। एक बार आवेदन करने के बाद शुल्क वापिस नहीं होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी गाइडलाइंस के मुताबिक ही आवेदन करें।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए लॉगइन करने के तीन दिनों के भीतर आवेदन प्रकिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगइन करना अनिवार्य है।
- दूसरे स्तर पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें मात्र 12 प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा।
- तीसरे स्तर पर लिखित परीक्षा होगी, जो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दी जा सकेगी। अंग्रेजी में परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी सीधा टेक्स्ट बॉक्स में लिखना शुरू कर सकते हैं जबकि हिंदी के लिए अगले टेक्स्ट बॉक्स हिंदी के शब्दों को इंगलिश अक्षरों में टाइप कर कॉपी करने के बाद इंगलिश बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनीटरिंग होती रहेगी।
- चौथे स्तर पर साक्षात्कार होगा। इसमें प्रश्न वाले विडियो रिकार्डिंग आरंभ करने तथा अपनी विडियो रिकार्डिंग आरंभ करने का विकल्प आवेदक के पास होगा। आवेदक के पास अपनी सुविधा के मुताबिक इन प्रश्नों के उत्तर रिकार्ड करने होंगे।
- पांचवे स्तर पर आवेदक को कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इसके छह भाग हैं। आवेदक को इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। यह अध्ययन सामग्री आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होगा। ताकि आवेदक को इस बात का आधारभूत ज्ञान हो सके कि उसे क्या कार्य करना है।
- छठे स्तर पर आवदेक को पोर्टल के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंसिंग में भाग लेने के लिए अपना समय निर्धारित करना होगा। इसके लिए लिंक ई–मेल पर या लॉगइन कर पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- सातवें स्तर पर यदि चयन होता है तो कुछ आधारभूत दस्तावेज अपलोड करने का लिंक सक्रिय होगा। इस लिंक पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आठवें स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद तीन दिनों के भीतर आवेदक को ऑफर लैटर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण के बारे में सूचित किया जाएगा।
- नवें स्तर पर प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र एनएसडीसी पीएमकेवीवाई के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- दसवें स्तर पर नियुक्ति पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके साथ नया लॉगइन तथा कार्यों की रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एवं पोर्टल 1 सितम्बर से खुलेगा। आवेदन करने के बाद आवेदक को लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड दिया जाएगा उसके पश्चात 3 दिन के भीतर ही आवेदक को
''ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया'' पूर्ण करनी होगी।
संबन्धित जानकारी एवं आवेदन करने के लिए recruitment.missionriev.in **पर लगातार ब्राऊज़ करते रहें।**

Second chance for all old PFs who have been disassociated and inclined to re associated.
- Use old ID for filling the online application
- No application fee required
- Skill development training not essential but have to go through online

ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत भर्ती प्रक्रिया

विज्ञापन	रीव टाइम्स, सोशल मीडिया, दैनिक समाचारपत्रों के माध्यम से
कंप्युटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन → आवेदन संबंधी दिशा निर्देश	IIRD मिशन रीव के बारे मे संक्षिप्त परिचय विडियो एवं बुनियादी जानकारी
रेफरेंस चेक	आवेदक को 3 गणमान्य व्यक्तियों ने नाम देने होंगे जो आवेदक का अनुमोदन कर सकें
प्रलेखन/ Documentation	आवेदक को अपने शिक्षा एवं कार्यानुभव के सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे
लिखित परीक्षा/ Written Test	वेब केमरा युक्त कमप्यूटर पर ऑनलाइन MCQ संबन्धित एवं व्याख्यात्मक लिखित परीक्षा देनी होगी
दृश्य–श्रव्य साक्षात्कार का पहला पड़ाव Audio Visual (Interview)	ऑनलाइन साक्षात्कार होगा जहां कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे
मिशन रीव मे कार्य तथा सेवाओं को देने बारे गहन समझ के लिए/ In depth understanding of Role	ई लर्निंग आधार पर ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वीडियो–ओडियो तथा टेक्स्ट अध्ययन
आवेदक के अपने कार्य संबंधी समझ का आकलन Assessment on role understanding विडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आधारित ऑनलाइन इंटरव्यू का अंतिम पड़ाव/ Video Conferencing by HOD/ Senior Person	ऑनलाइन इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव मे मिशन हैड क्वार्टर से सीधे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जहां किसी उच्च अधिकारी अथवा अधिकारियों के पेनल से साक्षात्कार होगा जिसमे कार्य को समझने संबंधी क्षमता का ऑनलाइन आकलन होगा
नियुक्ति प्रस्ताव/Offer Letter	नियुक्ति प्रस्ताव पत्र लेने के लिए अभ्यर्थी को मिशन हैड ऑफिस बुलाया जाएगा जहां 1 घंटे का आरंभिक परिचय व जानकारी दी जाएगी
NSDC से प्रमाणित 30 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात 30 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान NSDC से प्रमाणित प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए प्रशिक्षु को 8000/– रुपए फीस देनी होगी।

NSDC से प्रमाणित 30 दिन के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को फील्ड मे नियुक्ति दी जाएगी जहां सम्पूर्ण किए गए कार्यों तथा कंप्यूटरीकृत उपस्थितियों (हाजरियों) को ध्यान मे रखते हुए अधिकतम रुपये 10,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके इलावा टी॰ए॰, डी॰ए॰ तथा वार्षिक इन्सेंटिव का भी प्रावधान होगा।

अपनी पंचायत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायित्व:

- स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को प्राप्त करने में सहायता।
- जैविक खेती, कृषि संबंधी, मिट्टी जांच संबंधी हर सुविधा को हासिल करने में सहायता।
- पशु पालन में जैविक दुग्ध–वर्धक पशु स्वास्थ्य–वर्धक फीड सपलीमेंट उपलब्ध करवाने में सहायता।
- Mission RIEV द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा सेवाओं की जानकारी घर तक पहुंचा कर सेवाओं को लेने के लिए सदस्यता पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करना।
- मिशन रीव द्वारा संचालित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और ग्रामीण लोगों की जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए सेवाओं को देना।
- ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों तथा महिला मण्डल, युवक मण्डल जैसे सामुदायिक समूहों के साथ एक गतिशील संपर्क एवं संवाद स्थापित करना।
- राजस्व उत्पादन के लिए लोगों / सदस्यों को सेवाएं प्रदान करके मिशन को सफल बनाने के लिए योजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत मे मिशन के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करके मिशन को अधिक व्यवहार्य, लाभदायक, प्रभाव–उन्मुख और स्वावलंबी बनाना।
- मिशन रीव के HQ के अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रकार के संवादों का आदान–प्रदान रपटों तथा सूचनाओं का रख–रखाव एवं साझा करना।
- पंचायत स्तर पर सम्पन्न की गईं दैनिक गतिविधियों को समय पर पूरा कर उच्च अधिकारियों को आवधिक रिपोर्ट जमा करना।

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर

रोजगार के लिए आवेदन तथा रिक्तियों संबंधी जानकारी लेने के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर तथा ईमेल पर संपर्क करें :–
0177– 2640761, 2844073 anand@iirdshimla.org info@iirdshimla.org hr@iirdshimla.org